THE DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned for lunch till 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at thirty-four minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-six minutes past two of the clock.

[The Vice-Chairman (Shri Jagesh Desai) in the Chair.]

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The finance Bill, 1989

SECRETARY-GENERAL: Sir, I beg to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Finance Bill, 1989, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 2nd May, 1989.

The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table of the House.

APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1989—Contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): We now take up the Appropriation (No. 2) Bill, 1989. Shri Rameshwar Thakur. Now, there are 11 Memers to speak. The time allotted is four hours. I would request hon. Members not to take more than the time allotted to them.

श्री रामेश्वर ठाकुर (बिहार): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं विनियोग संख्या 2 विधेयक 1989 का समर्थन करता हूं। इस विनियोग विधेयक के मार्फत 24 खरब 4 अरब 72 करोड़ 53 लाख रुपये का विभिन्न मदों में प्रावधान किया गया है, जो कि वित्तीय वर्ष 1989-90 के दौरान किये जाने वाला है। इस विधेयक के विषय में अभी प्रारम्भ में ही हमारी दूसरी ओर से एक वरिष्ठ सदस्य ईश दत्त यादव जी बोल रहे थे। मैं समझता हूं कि यह आवश्यक है कि जब हमारे दूसरी तरफ बैठने वाले सदस्य बोलें वे सरकार के कार्यों की आलोचना करें लेकिन यह आलोचना स्वस्थ होनी चाहिए, तर्क सहित होनी चाहिए, उसमें दिशा होनी चाहिए। मुझे इस बात का दुख है कि एक वरिष्ठ सदस्य आलोचना के प्रारम्भ में ही यह कहने लगे कि यह बजट सरकारी आफिसरों ने बनाया है और इस बजट के द्वारा देश के विकास का कोई काम नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं, कहते-कहते वे कुछ तथ्यों पर आये और कहने लगे कि पिछले 42 वर्षों से अब तक देश में किसी भी प्रकार के विकास का काम नहीं हुआ। हमें आश्चर्य होता है जब इस सदन में इस तरह की बातें कही जाती हैं। यह बात बिल्कुल ही तथ्यों से रहित और आधार विहीन है और यह उचित नहीं है। सरकारी आफिसर हमारे कार्य में मदद करते हैं। उनके कुछ कर्त्तव्य और दायित्व हैं। किसी भी संसदीय प्रणाली में सरकार बजट प्रस्तुत करती है। हमारे बजट में दिशा है, हमारे बजट का लक्ष्य है और हमारे बजट में विभिन्न प्रकार के प्रावधान किये गये हैं जिससे देश का विकास, चाहे वह कृषि का हो, उद्योगों का हो, ग्रामीण विकास का हो और चाहे दूसरी दिशाओं का हो, सब के विकास के लिए समुचित प्रावधान किये गये हैं और इन्हें हमें उचित रूप से देखना होगा। कहा गया कि पिछले 42 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ। क्या कृषि के क्षेत्र में हमारी प्रगति नहीं हुई, सिंचाई का काम आगे नहीं बढ़ा? हमें सही आंकड़ों को मानना चाहिए। अगर ऐसा करें तो हमें कोई दुविधा नहीं हो सकती। पंडित जवाहर

[श्री रामेश्वर ठाकुर]

लाल नेहरू के नेतृत्व में हमारे यहां योजनाओं का कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना से अब हम सप्तम पंचवर्षीय योजना के अंतिम साल में हैं। काफी विकास हुआ है। जहां हम 50 बिलियन टन अनाज पैदा करते थे वहां आज छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक 150 बिलियन टन अनाज पैदा करने लगे हैं और चालू वर्ष में जबकि पिछले दो सालों में सभी जानते हैं कि 1986-87 और 1987-88 में देश के बहुत बड़े भाग में 216 जिलों में भयंकर सूखाड़ या लगभग दो तिहाई हिस्से में सूखा था इसके बावजूद भी हमारे यहां चालू वर्ष में अभी 1988-89 का साल जो हुआ इन वर्षों में 166 बिलियन टन अनाज पैदा हुआ और उम्मीद है कि जो हमारा लक्ष्य सप्तम पंचवर्षीय योजना के अंत तक 175 बिलियन टन का है हम उससे भी आगे बढ़ेंगे। यहां हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आजादी के थोड़े दिन पहले अनाज की कमी के कारण लाखों लोग कलकत्ता में मरे थे और इतना बड़ा अकाल हुआ एक भी व्यक्ति देश में अनाज के बिना भूख से नहीं मरा। यह वास्तव में हमारी सरकार की उपलब्धि है। इसलिए यह कहना कि इन वर्षों में कोई कार्य नहीं हुआ है यह बिलकुल तथ्यहीन बात है, बेबुनियाद है। इसी तरह से बिजली का उत्पादन जहां 1951 में 1700 एम.वी. था वह आज बढ़ कर 1987-88 में 54247 एम० वी० हो गया। अब यह कहें कि बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ा यह उचित नहीं है हम यह कह सकते हैं कि जितना उत्पादन हुआ है जितनी वृद्धि हुई है देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वह कम है और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार स्वयं कह रही है हम सभी लोग कहते हैं कि और अधिक वृद्धि करने की आवश्यकता है लेकिन कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा कहना ठीक नहीं है। जहां तीन हजार गांवों में 1951 में बिजली पहुंची थी वहां हमारे पास चार लाख 68 हजार गांवों में बिजली पहुंची है। इतनी बड़ी तरक्की हुई है। इसी प्रकार से कृषि के क्षेत्र को हम लें तो हम देखेंगे कि तरक्की हुई है और ऐसी तरक्की हुई है कि जितने विकासशील देश आस-पास के हैं जो हमारे क्षेत्र में आते हैं जो देश लगभग उसी समय आजाद हुए थे जब हम आजाद हुए थे उन देशों में जो तरक्की हुई है उसको देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि हम किसी दूसरे देश से पीछे नहीं है। कई मामलों में तो हम आगे हैं और कई मामलों में हमारा विकास इतनी तीव्रता से हुआ है कि आज जो विकसित देश हैं वह भी मानते हैं कि हिंदुस्तान बहुत से क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़ा है। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में हमारे देश ने जितनी तरक्की की है आज विज्ञान और तकनीक के लगभग एक तिहाई लोग इस देश में हैं और विभिन्न क्षेत्रों में चाहे वह आवागमन के क्षेत्र हो, चाहे वह दूर-संचार का क्षेत्र हो, चाहे वह हमारे बड़े उद्योगों का क्षेत्र हो हम हर दिशा में देखेंगे कि हमारी सराहनीय तरक्की हुई है। और भी गुंजाइश तरक्की करने की है। बिजली और इलैक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में कम्प्यूटर के क्षेत्र में थोड़े ही वर्षों में हमारी जो तरक्की हुई है वह किसी भी अन्य विकासशील देश के मुकाबले में कहीं अधिक है। इस दिशा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारा प्रयास है और प्रयास जारी रहना चाहिए। यह हमारा कर्त्तव्य और दायित्व है। लेकिन उद्योग की दिशा में हम देखेंगे कि पिछले वर्षों में जो तरक्की हुई है वह तरक्की काफी सराहनीय है और इस वर्ष भी इसके बावजूद कि पिछले वर्षों में देश के कुछ हिस्सों में सूखा पड़ा 1988-89 में 9 प्रतिशत उत्पादन में वृद्धि हुई है और 1989-90 में जिस बजट का जिक्र हमारे माननीय सदस्यों ने किया है 10 प्रतिशत वृद्धि होने की सम्भावना है और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से चारों दिशाओं में हमारी तरक्की हो रही है औद्योगिक उत्पादन में भी हमारी तरक्की होगी। जो उन्होंने छोटे उद्योगों की बात कही, छोटे उद्योगों में भी आशातीत तरक्की हुई है। ऐसा नहीं है कि

छोटे उद्योगों की दिशा में हमारी तरक्की नहीं हुई है छोटे उद्योगों की दिशा में भी तरक्की हुई है। जो ग्रामीण उद्योग हैं जो खादी और ग्रामोद्योग हैं जो लघु उद्योग हैं उन उद्योगों को प्रोत्साहन देना ही चाहिए और सरकार सतत दे रही है। पहली योजना से सातवीं योजना तक आप देख इसमें विभिन्न प्रकार के प्रावधान किये गये हैं। यहां तक कि बैंक से भी कम उनको कम ब्याज पर रुपया दिया जाता है जिससे कि वह अधिक से अधिक अपना विकास कर सकें। दूसरी तरह की जो सुविधायें चाहियें, आधारभूत जो सुविधायें हैं इनफ्रास्ट्रक्चर की हैं जो देहातों में गांवों में जायें जिससे कि हमारे गांवों के लोग अधिक से अधिक तरक्की कर सकें और छोटे उद्योग गांवों में बैठाये जा सकें। यह होना ही चाहिए। क्योंकि उसमें हम मानते हैं कि हमारे रोजगार की गुंजाइश ज्यादा है। हमारे खादी ग्रामोद्योग में रोजगार की सुविधा बहुत है और गुंजाइश भी है और हो भी रही है। इस वक्त 50 लाख लोग खादी ग्रामोद्योग के काम में लगे हुए हैं। इसी प्रकार से दूसरे लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों और छोटे उद्योगों में बहुत बड़ी संख्या में लोग लगे हुए हैं। लेकिन साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इतने बड़े देश को आज के युग में सारे विश्व के स्तर में लाना है तो बड़े उद्योगों की भी उतनी ही आवश्यकता है मध्यम उद्योगों की भी जो ही आवश्यकता है है। इसमें भी हमारा समाजवाद का एक लक्ष्य है। जिस दृष्टि से हमने 1950-51 में शुरू किया था, केवल 9 पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग्स या सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान थे, अब उनकी संख्या 211 है। आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक प्रतिष्ठान है और उन्होंने तरक्की की है और उनकी तरक्की का फल है कि 58 हजार करोड़ से अधिक रुपया इनमें लगा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग इनमें काम कर रहे हैं और देश की जो हमारी आवश्यकता है चाहे वह खादी की हो, लोहे की हो या दूसरी आवश्यक वस्तुओं की हो उनके उत्पादन की हो उनके उत्पादन में हमारे सार्वजनिक प्रतिष्ठानों ने बहुत अधिक तरक्की की है। आप जानते हैं कि पिछले साल लगभग 2183 करोड़ का मुनाफा इनमें हुआ है। यह एक संतोष की बात है। लेकिन हम यह आवश्यक समझते रहे हैं और कहते रहे हैं इस सदन में भी कि पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग्स की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए। जितनी उत्पादन क्षमता है उसका हम पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं। उस क्षमता को हमें बढ़ाना चाहिए। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमारा बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमारी जो कार्य करने की प्रणाली है इसमें और तीव्रता आनी चाहिए और हमारा मुनाफा नमें और बढ़ना चाहिए। यह है। लेकिन जो काम हुआ है उसके लिए कहें कि काम कुछ नहीं हुआ है 42 साल में तो मैं समझता हूं कि ऐसा किसी भी जिम्मेदार सदस्य के लिए इस सदन में कहना उपयुक्त और शोभनीय नहीं है।

इसी तरह से दो, तीन और बातें कहीं गयी हैं जैसे योजना, बाहरी ऋणों, ब्याज, घाटे की अर्थव्यवस्था तथा हमारी योजनाओं में कमी की बातें की गयी हैं। इन विषयों में मैं यह कहना चाहूंगा पहले कि जो 93 प्रतिशत हमारी स्वदेशी लागत योजना का खर्च है, जो बहुत बड़ी योजना है; 4 हजार करोड़ से हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरू किया था और अब 3 लाख 20 हजार करोड़ की लागत सप्तम पंचवर्षीय योजना में है, तो इतनी बड़ी लागत का 93 परसेंट देश के अंदर से ही आया है और बहुत छोटे अनुपात में ही हम विदेशों से इसमें सहायता ले रहे हैं। लेकिन जो देश से साधन बजट में आते हैं उस पर ब्याज देना पड़ता है। हमारे पास लगभग देश की 24 प्रतिशत बचत है। यह देश के लिए एक बहुत बड़ी ताकत की बात है। स्वाभाविक है कि जो 17 हजार करोड़ का प्रावधान इसमें है वह ब्याज का है। वह कुछ मामलों में अधिक माना जा सकता है। हम समझते हैं कि इसमें दो उपायों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, कि तीन चीजों ब्याज, सब्सिडी तथा हमारा जो डिफेंस

[श्री रामेश्वर ठाकुर]

का खर्च है, इन तीनों पर जो ैर योजना के मद में हमारा खर्च है–54 हजार करोड़ का इसमें उल्लेख किया गया ---वह कम है । जहां तक सैनिक खर्च का सवाल है आपने देखा कि इस वर्ष की बजट में, इसके बावजूद की हमारी आवश्यकता अधिक है, श्री राजीव गांधी जी की सरकार ने साहसपूर्ण निर्णय ले करके सैनिक खर्च में बहुत अधिक वृद्धि नहीं की । लगभग पिछले वर्ष के बराबर ही खर्च रखा गया है । जहां तक सब्सिडी का सवाल है किसानों के लिए तो वह जरूर बढ़ा है । हम जानते हैं जो 1100 करोड़ 1984–85 में था वह बढ़कर 5 हजार करोड़ से अधिक 1989–90 में हो गया है । लेकिन यह नितांत जरूरी है जब हम कृषि को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हमारे जो किसान हैं उनको खास तौर से खाद में, कीटनाशक दवाओं में सहायता देना आवश्यक है और इस सहायता पर अभी कहा गया, एक सदस्य ने कहा कि आपके वित्त मंत्री कहते हैं कि यह बेकार हो रहा है । ऐसी बात वित्त मंत्री जी ने नहीं कही है । वित्त मंत्री जी ने जो बात कही है और जो हम सभी लोग कहते हैं कि जो सहायता हम देते हैं फर्टिलाइजर की कंपनियों के द्वारा, उनके मूल्य में कमी करके, क्या उसके और कोई तरीका हो सकता है कि किसानों को कम मूल्य में उनको फर्टिलाइजर मिले, खाद मिले । किन किसानों को सीधे इसकी सहायता अधिक से अधिक कैसे मिल सकती है, इस पर विचार करना चाहिए ।

हम सभी यह जानते हैं कि हमारे रुपये का अवमूल्यन हुआ, यह ठीक है, लेकिन यह सारे विश्व की परिस्थिति है, यहां पर ही नहीं है । अभी बजट में जो हमारे यहां घाटा है, आप पांच साल के आंकड़ों को देखें, तो जो हमारी लागत है–नहीं समय के अभाव में सभी नहीं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि बजट का घाटा 10 प्रतिशत के अंदर ही हमारी डेफिसिट फाइनेंसिंग रही है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Mr. Thakur, five minutes more.

श्री **रामेश्वर ठाकुर**: 1984–85 में 4,484 करोड़ घाटा था, वह जो बढ़ा है वह हमारी 10 प्रतिशत जो टोटल आउट है प्लान की, हर साल उसके 10 प्रतिशत के अंदर है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि 10 प्रतिशत आपका घाटा है, तो यह इतना घाटा नहीं है जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और फिर भी अविकसित अर्थव्यवस्था में जहां पर डिवेलपिंग इकानामी है और जहां हम अपने देश के विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ाकर देना चाहते हैं, वहां पर हमको अधिक से अधिक लागत लगानी ही पड़ेगी और इसमें जो 10 प्रतिशत का घाटा है, उसको हम अधिक नहीं मानते ।

यदि हम देखना चाहें कि हमारे आसपास के जो पांच देश हैं, उन पांचों के आंकड़े ले लें, चाहे वह बंगला देश हो, चाहे नेपाल हो, चीन हो, श्री लंका हो या इंडोनेशिया हो, बाहर से जो उन्होंने लिया है, उसके अनुपात में हमारा हिंदुस्तान ने जो कर्ज लिया है और अपने फर्ज को जिस तरह से यूटिलाइजड किया है, वह सब से सराहनीय है और इस मद में हमारी जो लागत है, वह दिनों दिन घटती गई है, बढ़ी नहीं है । इसके बावजूद कि एब्सोल्यूट टर्म्स में हमारा रुपया मात्रा में ज्यादा लगता है, लेकिन जो कुल राशि योजना में लगी हुई है, उस अनुपात में जो हमने रुपया लिया है, वह अन्य देशों से हमारी स्थिति अच्छी है और हम समझते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा घबराहट की बात नहीं है ।

आवश्यकता इस बात की है, माननीय मंत्री जी से मैं कहूंगा, दो-तीन सुझाव मैं इस संबंध में दूंगा ।

इस संबंध में पहली बात यह है कि जो सरकारी खर्च है, उसमें जितनी कटौती की जा सके, वह की जानी चाहिए क्योंकि

यह नितांत आवश्यक है कि जहां हम गरीबों की अधिक से अधिक मदद करना चाहते हैं, तो वहां आवश्यक है कि हमारे खर्च के जो ढांचे हैं, उनमें हमें कमी करनी ही चाहिए और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, कम से कम हम अनुरोध करेंगे कि 1989-90 में जितना हमारे बजट का प्रावधान है, उसका 5 प्रतिशत खर्चे में कमी की जानी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि ग्रामीण विकास के लिए जो काम में आपने मदद की है, हम प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने अभी पिछले हफ्ते ही इसी सदन में और दूसरे सदन में जो जवाहर योजना के विषय में घोषणा की है—जवाहर रोजगार योजना जो है, यह अपने आप में एक क्रांतिकारी काम है। एक साल के अंदर 2100 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

श्री यशवंत सिन्हा (बिहार) रोजगार योजना है, बेरोजगार योजना नहीं है।

श्री रामेश्वर ठाकुर: जी, मैं बेरोजगार नहीं, रोजगार योजना कह रहा हूं। यह बेरोजगारी दूर करने के लिए जवाहर रोजगार योजना है—मैं उसकी बात कर रहा हूं। बेरोजगारी को दूर करने की बात है।

तो यह हमारी योजना है जिसमें कि प्रत्येक पंचायत में अस्सी हजार से एक लाख रुपये तक का प्रावधान किया जाएगा एक साल के अंदर और चार करोड़ और चालीस लाख ऐसी पंचायतों के अंदर गांव हैं जिनको कि हम इसके आप में बड़ा काम है। इस काम को सीधे पंचायती स्तर पर, जिसका कि 80 प्रतिशत रुपया भारत सरकार देने वाली है, मैं समझता हूं कि सारे देश में इससे बड़ी रोजगार की सुविधा प्रदान करने की योजना अभी तक नहीं बनी थी और इसके लिए हम सरकार को और प्रधान मंत्री जी को बधाई देते हैं।

साथ ही साथ अपेक्षा यह है—अब चूंकि समय कम है और रोजगार की योजना को जमीन तक ले जाते-जाते, पंचायत तक से जाते-जाते, उसमें समय लगता है। उसमें हमें ज़रूरत यह है कि जो हमारे लोग हैं, केवल सरपंच नहीं, केवल पंचायत के लोग नहीं, जो हमारे लोग है, बेनिफिशयली जिसको कहते हैं, पंचायत में रहने वाले चार-पांच हजार आदमी हर पंचायत में जो लोग रहते हैं। उनका यदि हम इसमें सहयोग लेंगे, उनका इन्वाल्वमेंट होगा तो हम इस काम को अधिक सफलता से कर सकते हैं और इसके जरिए वास्तव में बेरोजगारी दूर करने की जो हमारी योजना है पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के शताब्दी वर्ष में उसकी पूर्ति हम कर सकेंगे। तीसरा, मेरा सुझाव यह है कि जो दूसरी फाइनांशियल इन्टीट्यूशंस बैंक्स खास तौर से विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनका बहुत ही सराहनीय काम रहा है, लेकिन सारे देश में एक बात पर हमारा ध्यान जाना चाहिए कि योजना में जो हमने नीतिबद्ध निर्णय लिया है कि सभी क्षेत्रों में जो कार्य हो, वह संतुलित विकास होना चाहिए। हम देखते हैं कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ प्रांत ऐसे हैं और कुछ प्रांतों में ऐसे जिले या क्षेत्र हैं जिनका समुचित विकास नहीं हुआ है। हमारी सात योजनाएं हो गई इसके बावजूद भी खास तौर से पूर्वांचल के प्रांत जिसमें कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम तथा पूर्वांचल के अन्य छोटे 6 जो प्रांत हैं वे सभी आते हैं और कुछ दूसरे प्रांत भी हैं जिनके कुछ हिस्से अभी भी पिछड़े हुए हैं, तो हम समझते हैं कि यह आठवीं योजना में सरकार को इस रोजगार योजना को सारे देश में तो चलाना ही है लेकिन आठवीं योजना में ये अविकसित क्षेत्र हैं जिनका विकास नहीं हुआ है, जहां आधारभूत सुविधायें अधिक नहीं होती हैं, जहां सिंचाई का काम, बिजली का काम, आवागमन का काम, रेलों का काम उतना नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिए और जो आधारभूत सुविधायें हैं वे बहुत ज्यादा लागत युक्त हो गई हैं जिनकी लागत बढ़ गई है उन राज्यों में जब तक इसके लिए विशेष प्रबन्ध नहीं किया जाएगा, प्रावधान नहीं किया जाएगा तो ये क्षेत्र अविकसित ही रहेंगे

[श्री रामेश्वर ठाकुर]

हम यह चाहते कि सारे देश के लोगों को खास तौर से ग्रामीण जनता को आगे बढ़ायें, उस काम के लिए कुछ विशेष प्रावधान 8वीं योजना के अंतर्गत करना आवश्यक होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं और जो काम अब तक हुए हैं उस पर हम सभी लोगों को गौरव होना चाहिए और जो कमियां हैं, जो कि हमें दूर करनी चाहिएं, वह हम सब मिल कर के, देश के सारे लोग मिल कर के उन कमियों को दूर करें तथा आगे हम यह कोशिश करें कि हमारे ग्रामीण भाई जिन के लिए इतने तरह की योजनायें लाई गई हैं, खास तौर से अभी जो सब से अच्छी जवाहर रोजगार योजना लाई गई है और दूसरी जो बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत योजनायें हैं उन सब योजनाओं को हम साकार कर सकें, सफलीभूत कर सकें और उनसे लोगों को सही मायने में सहायता मिल सके, इसके लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, अब मैं पुनः इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Mr. Jaswant Singh. You have only eight minutes, but you can speak up to ten minutes.

SHRI JASWANT SINGH (Rajasthan): As usual you have started me with so much encouragement. I am grateful to you for it. I am also grateful to my other colleagues who have allowed me to break the queue.

The Appropriation Bill normally comes, in this entire process of Budget-making, at a stage which I consider to be a stage of Parliamentary fatigue. The present attendance in the House is a reflection of that Parliamentary fatigue. Nevertheless, it is an essential step and it is a step which we must go through. But it is also a measure of the declining relevance, as it were, of legislative control over the financial performance or financial planning of the Government that we find that the entire Budgetary exercise, which is one of the principal legislative rights, stands today so considerably diminished as a Parliamentary activity of importance. To me, personally, that is one more, depressing aspect of our Budget session. But that is a much bigger question. I will revert to it in a minute as you started by saying that I have only ten minutes.

By itself the Appropriation Bill is an exercise to authorise the Government to take certain sums from and out of the Consolidated Fund for the year 1989-90 for payment and for appropriation. Sir, there are some unusual features of this Budge-
3.00 P.M. tary exercise of 1989-90 and in the overall aspect of the declining parliamentary or legislative scrutiny of the budgetary responsibility, these two aspects, in the current year are particularly noteworthy. I am given to understand that some of the colleagues who spoke earlier have, perhaps, drawn attention to it but I cannot with any degree of reassurance remark upon the fact that the other place discussed only two Ministries in detail. I would stand corrected, Sir, if it were three. But out of a total, I believe, of the bureaucratic profusion of Ministries, if the Parliament as such is able to engage itself in an examination; detailed examination, of the Demands for Grants, of only three Ministries, I do not think that the message contained in that failure is a message of reassurance.

Secondly, Sir, I must with very great concern observe—and my friend, eminent senior colleague Raja Saheb is here, perhaps, he could correct me on this fact—I do not believe that in the last 40 years never has the Parliament failed to discuss the demands for Grants of the Ministry of Defence. And yet, this is the first time ever that this Parliament as constituted has not, to my mind, fulfilled its responsibility, indeed its obligation, as the guardian of the funds of the country, as the original fountain-head which,

in fact, sanction this spending of those funds; for it to have failed even to discuss in detail the Demands for Grants of the Ministry of Defence; for the first time ever in 40 years is, to my mind, a very signal failure. When we discuss this particular Appropriation Bill which in essence, even in normal circumstances is a proforma exercise, I cannot refrain from observing on these larger failures.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): But in our House we had discussed on working of the Defence Ministry.

SHRI JASWANT SINGH: I always bow to your superior wisdom and knowledge. The working of any Ministry taken up by this House has altogether a different context. When I refer to the present failure it is to neither of the two Houses taking up Ministry of Defence, or the detailed Demands for Grants of that Ministry—our House is not discussing it, the other has not, and this has happened for the first time in the 40 years—I think it is not a development, it is not an incident which I can let pass without comment because it is a deeply disturbing development. It is normal under such circumstances—I will be coming back to the Ministry of Defence—to speak a bit about and make some comments on the budget as such. Now, I won't go into all the general observation about the budget because the debate has already taken place, and I am sure the Minister of State is weary now of hearing all the comments over and over agian in the other place, as also here. Of course, there is only this much that one can be original about, otherwise all this tends to be repetitious. Nevertheless there is an aspect, because this is an Appropriation Bill, of expenditure which is deeply worrying us. In 1989-90, I could be wrong, the Government expenditure will be increasing by 8 per cent over the previous year and it will go up to something in excess of Rs 82,000 crores. Now, the budget papers that we have been given by the Government itself say about the total liability—the phrase we use normally is "total liability of the Government of India" which means even I, Government of India is a changing entity But the people shall remain, Parliament shall remain. Therefore, if there is a liability created and if it is called the liability of the Government of India, it is not the personal liability of the hon. Minister of State. It is your liability and my liability. It is a liability of generations of Indians which include not only the national debt but also the liability to repay the amounts due on account of provident fund, small savings and the like. It would increase by 13.7 per cent to a sum in excess of Rs. 2,60,000 crores and here I would be very happy if my esteemed colleague and eminent constitutionalist like Ram Jethmalani would correct me, which brings me to article 292 of the Constitution of India. Article 292, to my understanding enables the Parliament to prescribe, by law, the limits within which the executive can borrow and I think the time has come when we have to very seriously think about invoking article 292 because this excessive expenditure, this kind of national debt, public borrowing to which the previous speaker referred, has acquired such staggering heights, such staggering dimensions that I fail to understand how we are going to free ourselves of it. I have had occasion to mention it and I feel that I mentioned it to the present Foreign Secretary at a function which we jointly attended to me personally, a sum like Rs. 2,60,000 crores, I cannot conceptualise. I do not know what it means. It is quite often said, if I have a debt of Rs. 10,000, then I have a problem. But if the bank owes me Rs. 10,000 crores, then the bank has a problem. In similar terms, even though I cannot conceptualise this large sum of Rs. 2,60,000 crores, it is a very large sum of money and unless we start looking at it afresh unless we start thinking in terms of the constitutional provisions of article 292, I

[Shri Jaswant Singh]

think, perhaps in this overall aspect of Parliamentary scrutiny over the accounts of the country, we would be failing in our duty. Sir, I would now refer to what I started by saying—I have two more minutes, Sir—this myth of Parliamentary and legislative control—I started by saying that this Appropriation Bill comes at a certain stage and the entire legislative exercise of enabling the nation to spend a certain sum of money. Walter Bagehot, a great Constitutionalist, many years ago, in he early part of the century, in fact, reflected upon this when he said, "that the real legislation as such is never the function of the Parliament. It is always the bureaucracy which is producing a piece of law and the body of Parliament is merely a *post-facto* sanctioning and stamping authority." It has become particularly worrisome when the collectivity of Parliament, particularly the majority party stops applying its mind to the responsible function of legislation. In any case, it always will have to be the majority party which has to bring forward a legislation and if within that majority, the function is handed over to the bureaucracy and the bureacracy produces a pieces of paper as the law that Parliament has to pass and thereafter the majority does not even apply its mind to it, leave alone us in the minority, then I think, this sole function of Parliamentary scrutiny, this sole function indeed of legislature as such gets totally defeated.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): That means the Finance Minister has no role to play.

SHRI JASWANT SINGH: Sir, I do, with all the deference to the superior wisdom of the Chair, put it to you that even the budgetary exercise is given a political tint by any government and is an electoral stunt, particularly in an election year. Most of the legislative activity, inclusive of the Budget and the formulation and compilation of figures, is not a parliamentary activity. It is entirely a bureaucratic exercise. We in the legislature are certainly not peforming our functions and it is exemplified by the fact that the number of days we discuss is only two or three and we are only going through a proforma exercise.

I will take only a minute or two to talk about defence. It is a very big subject. I could not but talk about it because I came across a very provocative reminder from the past. It is almost two years old. In the Budget Session of 1987, I had occasion to talk and express my concern about the expanding defence expenditure and had then spoken of the need to re-examine some of the verities on which we were basing our defence expenditure. The Right Hon. the Prime Minister, on that occasion, spoke words to the effect—indeed this is a quotation, but not the full quotation:—

> "Anyone suggesting a cut in defence-spending or a cut-back in our defence forces, is being antinational and sabotaging the very integrity and independence of this nation."

They were words to the effect that not only must you not suggest it but you must not even think on those lines because if you think on those lines, then you are not "thinking as Indians, not thinking as friends of India; you are thinking as enemies of India." This was the comment made then. It became a matter of quite an interesting editorial debate in various journals then. Indeed, I was also asked. "How have you suddenly become an enemy of India?" I am therefore struck all the more by the bitter irony of the fact that the Budget Estimate has had a token-cut of about Rs. 200 crores. What is the token-cut in real terms? If you take into account the inflationary aspect, the decline in rupee-term, then it will amount to almost Rs. 2000 crores. No explanation has come forward from the Government as to why this cut has taken place except that the other day, when the

hon. the Foreign Minister, Mr. Narasimha Rao, speaking here, almost haphazard, said that through this we have sent an indication to Pakistan, by this defence cut. Some of my friends would recollect this. I was struck even then by the sheer mind-boggling irrelevance of it, the irrelevance of the fact that it has to be our Minister for External Affairs who is saying that by this token-cut of Rs. 200 crores we have sent a signal to Pakistan. The Demands for Grants for Defence should have been discussed. We should have had full opportunity to examine whether indeed this is token. After all, it is my fear that what has suffered by this cut are the armed forces, because the forces' level as such has not been reduced; indeed it is going up. Our commitments outside the territories of India remain. Therefore, what will suffer is the capital expenditure of the armed forces, of the Defence Ministry, which, in other terms, means you are not modernising the progress of the armed forces, of the Defence Ministry. It is very worrisome.

I come to the end of the time which you have so kindly given me, Sir. I will conclude by just one query to the Minister. Out of 252 Central public enterprises, I am given to understand, only 12 have made a profit. The net profit made by them in 1987-88, for which figures are available, is...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Have only 12 made profit?

SHRI JASWANT SINGH: Yes. Twelve. Perhaps, the Government could correct me.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I think it is wrong. It is more than fifty per cent of the public sector.

SHRI JASWANT SINGH: I am asking this query. The net profit earned for 1987-88 is Rs. 2183 crores which is 3 per cent return approximately on the investment made. Out of this 2183 ONGC refineries have earned 2171 crores, the National Thermal Power Corporation 302 crores, the STC and the MMTC between them, which are merely trading organisations which are not producing any wealth, have earned something like roughly 54 crores, which means the balance of 240 odd public enterprises have run into a loss. I would be very happy to be infomed by the Government that it is not so. Thank you for the time given to me.

SHRI RAOOF VALIULLAH (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, I rise to support the Appropriation (No. 2) Bill, 1989. The honourable Minister has rightly pointed out that most of the issues had been debated during the discussions on the General Budget. I would like to raise certain important issues regarding State financial resources...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Within ten minutes.

SHRI RAOOF VALIULLAH: The first is the devolution of finances to the State Governments. In 1986 the then Finance Minister, Shri Vishwanath Pratap Singh, while presenting his budget effected devastating changes in the investment pattern of small savings. Before 1986 it was 15 per cent in Government of India securities, 15 per cent in State Government securities, 40 per cent in the Post Office Time Deposits—POTD—15 per cent in the National Savings Certificates and 15 per cent in the Special Deposits. Now, these Special Deposits are not to be shared with the State Governments. The rest of them could be shared on an equal basis between the Central and State Governments. In 1986 the then Finance Minister effected devastating changes in the pattern of small savings with the result that today 80 per cent of the small savings are in Special Deposits and 20 per cent in Government of India deposits. I rememebr the present Finance Minister who was

[Shri Raoof Valiullah]

then the Chief Minister of Maharashtra raised a hue and cry against this change in the investment pattern in small savings. This has hit the States very hard because, as we are all aware, the two main sources of income for any State Government are small savings and sales tax. I do not know what made the Central Government change the investment pattern. I ouwld like the honourable Minister to let us know whether there has been a shift in the pattern and the thinking of the Central Government in order to boost the resources of State Governments...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): At present collection of small deposits is much more than collection from small savings.

SHRI RAOOF VALIULLAH: That is true. The second point is in regard to the resources of State Governments. We all know, particularly Gujarat and Assam are banking upon royalty payable to these States on crude oil. The royalty on crude oil payable to Gujarat is due with effect from 1st April, 1987. The Sarkaria Commission has recommended that royalty to the State Governments should be payable every two years. If we take that standard, if we accept the Sarkaria Commission's recommendation, then the next revision is also due with effect from 1st April, 1989. And we have not yet cleared the dues with effect from 1st April, 1987. I had raised this issue again and again in this House pleading that royalty payable to Gujarat and Assam should be fixed immediately and be paid to the State of Gujarat because the financial situation in Gujarat is very precarious. The honourable Minister hails from Gujarat and he knows what the situation today in Gujarat is. I understand there was a Secretary-level committee which was formed to find out what could be the correct quantum of royalty payable to these States. They have already submitted their report. When I asked a question, the Petroleum Minister submitted that the royalty is paid by the oil companies and not by the Government. Fixation is done by the Government. But this is a clever way of denying the due to Gujarat and Assam. It is fixed by the Government. Let the Government fix the royalty and then the oil companies will pay the royalty that is due. But something has to be done in the matter and this cannot go on like this because already two years have passed by and the royalty is not paid to the Government which is another source of revenue to the State Government. Sir, the Government of Gujarat had demanded Rs. 200 crores on account of this royalty payable to Gujarat. But the honourable Minister replied that they could not give Rs. 200 crores on account because it was not the Government which paid, but it was the oil companies which had to pay the royalty. Sir, this is not fair on the part of the Central Government where the State revenues are concerned and the Government must find a way out, first of all, to fix the royalty and then pay the dues.

Sir, the third important question about the State Government is the pending projects with the Central Government. I want to cite one instance. Natural gas is produced in the State of Gujarat and there is feeling amongst the people of Gujarat that the gas is being carried away and not being utilised properly in the State where it is produced. The Government of Gujarat had submitted viable propositions for gas-based power stations. They were cleared by the Central Electricity Authority and the Ministry of Petroleum had already committed and communicated that gas would be available for these gas-based power stations, one at Gandhar and the other at Pipavav in Saurashtra. The first one is of 600 MW capacity and the second one is of 700MW capacity. But I am surprised that only a few days ago, the honourable Minister, while replying to a Starred Question, said that no clearance had been given! Now, this is the kind of reply from the Minister of Energy because they are the ultimate autho-

rity. As it is, a very a bad feeling is there among the masses, particularly of this State where gas and oil are produced and I would therefore, request the honourable Minister to see that where gas is produced in a State and where there are viable propositions for gas-based power stations, at least clearance should be given by the Union Government as early as possible so that this kind of feeling among the people of Gujarat could be assuaged.

Sir, the next important issue is concerning the implementation of the Integrated Rural Development Programme. I understand the Planning Commission has recommended that the per capita input by the nationalised banks, in order to cross the new poverty line, should be raised to Rs. 7000. But, today, the answer in this House by the honourable Minister is that no State has more than Rs. 4000 as per capita input by any nationalised bank. Now, what does this mean? It means that this amount of Rs. 4,000, which will help the beneficiaries cross the new poverty line, goes waste. Therefore, in order really to implement the Integrated Rural Development Programme, the investment by the nationalised banks, the input by the banks, should be increased to a higher level so that the new poverty line could be crossed by the beneficiaries, by the poor people of this country. This is a very important issue and I would like to request the honourable Minister and the Union Government to impress upon all the public sector banks to enhance their investment, the per capita investment, on the beneficiaries who are taking advantage of the Integrated Rural Development Programme.

Sir, the last point is this: Certain letters of intent have been issued by the Union Government to the State Governments. I would cite two examples from my State of Gujarat. A letter of intent was issued to Reliance Industries Limited for a petro-chemical project on the 25th of November, 1988. I have raised this issue publicly and I have also written to the State Government. This petro-chemical project was demanded by the State Government as early as 1979. The two Chief Ministers, the present Chief Minister and the former Chief Minister, have written letters to the then Minister of Petroleum and even to the Prime Minister stating that the petro-chemical project should be given to the State of Gujarat in the public sector. I do not know what happened. And it was given to a private sector organisation. It was as if the State Government has pleaded that even if it is given to a private organization it has no objection provided it is located in Gujarat. Now, another Letter of Intent was issued to M/s S. R. for sponge iron project which initially was the demand by the State Government. Even gas was committed, because it was a public sector undertaking. And now we see that the sponge iron project is also given to the private sector. I, therefore, request the hon. Minister to verify all these things and then come out with a policy statement that where there are Letters of Intent or where projects have been asked by the State Government in the public sector, even if the State Government says so, they should not be diverted to the private sector.

Thank you, Sir.

श्री मोहम्मद अमीन (पश्चिमी बंगाल) : जनाब, दो नम्बर एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में जिसमें हुकुमत 24 खरब, 4 अरब, 72 करोड़, 37 लाख रुपये खर्च करने का अख्तियार मांगना चाहती है, यह अख्तियार तो उनको मिल ही जाएगा, इसलिए कि उनको बहुमत हासिल है । लेकिन मुझे इस सिलसिले में यह कहना है कि आज अगर मुल्क के माशी नक्शे पर नजर डाली जाय तो यह बात साफ तरीके से समझ में आता है कि यह नक्शा बहुत तेजी के साथ बिगड़ रहा है । सवाल यह नहीं है कि किसी मामले में कोई तरक्की नहीं हुई है। तरक्की हुई है लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं वह यह

[श्री मोहम्मद अमीन]

है कि तरक्की की यह रफ्तार बहुत सुस्त है और इतनी सुस्त है कि मसायल के पहाड़ ऊंचे होते चले जा रहे हैं। इसलिए जो गैप बढ़ रहा है, इसका फैसला कब होगा ? अगर इस नुक्ते निगाह से 42 सालों के हिन्दुस्तान के माशी हालात पर नजर डाली जाय और यह बात जो माशीयात मेहरीन कह रहे हैं कि हर साल हालत बिगड़ रही है। चाहे बेरोजगारी के मसले को लें, चाहे मंहगाई के सवाल को लें, चाहे गरीबी की रेखा से नीचे की जिन्दगी गुजारने वालों की तादाद को ल, चाहे समाजी जरायम के मामले को लें, तालीम को लें या रियायसी मकानात के सवाल को लें, तीबी इमदाद के सवाल को लें जिनका आम इंसान की जिन्दगी से ताल्लुक है, जो हजारत आज ट्रेजरी बेंचेज पर बैठे हैं वे हमें बता दें कि क्या इनमें से एक भी मसला हल हो गया है, सब की बात तो छोड़ दीजिए। एक मसला भी दिखा दें जो हल हो गया हो तो हम लोग मान लेंगे कि हुकूमत ने काम किया है। लेकिन एक भी मसला हल नहीं हुआ है। तरक्की होना या न होना एक बात है और मसलों का हल हो जाना दूसरी बात है। ऐसा क्यों हुआ ? यह सवाल बहुत बड़ा सवाल बन गया है और मैं उन लोगों के साथ मुत्तफिक हूं कि जो यह कह रहे हैं कि इस सरकार की पालिसी गलत है, बुनियाद गलत है। यह जो करना चाहिए वह नहीं कर रही है और जो नहीं करना चाहिए वह किया जा रहा है। इसका अंजाम भी उल्टा ही निकलेगा। आप यह भी देख लीजिए कि आज तक बेसिक लेण्ड रिफार्म नहीं हुए। इसको सरकार भी मानती है। लेकिन इसका जवाब कौन देगा ? 42 साल का अरसा कोई कम अरसा नहीं है। हिन्दुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और इसके मसले भी उलझे हुए हैं। इसमें पुराने जमाने की बहुत सी दुश्वारियां मौजूद हैं। उसके बाद भी 42 वर्षों के अन्दर अगर हुकूमत ठीक रास्ते पर चलती तो लोगों को खाना, कपड़ा और मकान, ये तीन चीजें तो दे ही सकती थी। बाकी मसले रह जाते। उनको मुल्क के लोग मिलकर हल कर लेते और हुकूमत की मदद करते। जो तरक्की होती है उसका भी फायदा कुछ मुट्ठी भरलोगों को ही मिलता है। ये जो इजारेदार घरानों के लोग हैं और वे लोग जो गांवों में जमींदार और महाजन हैं वे लोग पहले भी गरीबों पर जुल्म करते थे और आज भी कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा है। सभी लोग जो इस अवान के मेम्बर हैं वे देहातों में और अपने इलाकों में और अपनी रियासतों में जाते होंगे। देखते होंगे कि हालात कैसे हैं। इसलिए मैं ठोस तर्क पर चंद बातें रखना चाहता हूं। अभी गुजरात के बारे में हमारे एक भाई जो ट्रेजरी बेंच के हो हैं, उन्होंने सारी बातें कहीं। गुजरात की ही तरह तमाम रियासतों की मुश्किलातें बढ़ी हैं। चाहे वह बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, असम हो या उड़ीसा हो। अब यह फ्रेट एक्विलाइजेशन पालिसी को लें। मंत्री जी क्या आप यह बता सकेंगे कि इसके पीछे क्या जस्टिफिकेशन है ? फ्रेट एक्विलाइजेशन की पालिसी की वजह से जिन रियासतों में लोहे और कोयले की पैदावार होती है उनको करोड़ों करोड़ रुपये का नुकसान पहुंच रहा है। चेम्बर आफ कामर्स ने हिसाब दिया है कि इससे ईस्टर्न इंडिया को 5 हजार करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा है। इसका क्या जवाब है हुकूमत के सामने। जब यह मसला उठाया जाता है तो कभी कभी वायदा करते हैं कि इस पर नजरसानी की जायेगी। लेकिन होता कुछ नहीं है। या तो आप फ्रेट एक्विलाइजेशन की पालिसी खत्म कर दें या फिर ऐसी पालिसी अख्तियार करें जिससे तमाम रियासतों को बराबर सहूलियतें मिलें। इंसाफ एक ही हो सकता है। दो तरह का इंसाफ एक मुल्क में चलने वाला नहीं है। फिर आप देखिये, हम यह कहते हैं कि रियासतें अगर मोहताज रहें, अगर वे पैसा मांगने के लिए दिल्ली बार-बार आयें, पैसों के लिए उन्हें बार बार दौड़ दौड़ कर दिल्ली आना पड़े तो उससे कम का नुकसान होगा। इसलिए रियासती हुकूमतों को, चाहे वहां किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, उनको ज्यादा काम करने का मौका मिलना चाहिए। वे जनता के करीब होते हैं। उनके माली वसायल बहतर हों इसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। उनको कानूनी अख्तियारात मिलने चाहिए और इंतजामी अख्तियारात

उनके मिलने चाहिए। लेकिन हो रहा है ठीक इससे उल्टा। तमाम अख्तियारात दिल्ली के हाथों में महफूज किये जा रहे हैं और रियासतों को बात बात के लिए मोहताज रखा जा रहा है। आप जानते हैं कि बिजली की पैदावार बढ़ी है लेकिन जरूरत उससे ज्यादा बढ़ी है। अंजाम क्या है? लोड सेडिंग हो रहा है। बंगाल में 11 साल पहले जब वहां पर सी.पी.एम. की गवर्नमेंट हुकूमत में आई तो उस समय लोड सेडिंग का दौर दौरा था, कारखाने बंद हो रहे थे, करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा था, मजदूरों की तनख्वाह कट जाती थी। हुकूमत ने बड़ी मेहनत मुसलसल से इलेक्ट्रिसिटी की पैदावार को बढ़ाया और किसी तरह से सूरत हाल पर काबू पा लिया। इससे लोगों की तकलीफ कुछ कम हुई लेकिन जरूरत बढ़ गई है। बंगाल गवर्नमेंट ने मुतालबा किया था कि बांगेश्वर थर्मल प्लांट की बनने की इजाजत दी जाय और इसके लिये जरूरी माली मदद भी दी जाय। इसका वायदा भी किया गया था लेकिन बाद में तरह तरह के बहाने निकाल कर इंकार कर दिया कि यह नहीं हो सकता। इसी तरह के प्राजेक्ट दूसरी रियासत में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सेंट्रल प्रोजक्ट में इसकी दे दीजिए ताकि पैदावार में भी उनका कंट्रोल रहे और डिस्ट्रीब्यूशन पर भी उनका कंट्रोल रहे। इससे बंगाल के लोगों की जरूरत पूरी नहीं होगी। महोदय, आपको यह जरूर मालूम होगा कि मजबूर होकर बंगाल गवर्नमेंट ने फैसला किया कि 1 हजार करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के लिए अगर मरकजी हुकूमत पैसा नहीं देती है तो न दे, हम बंगाल के लोगों की मदद से इस प्रोजेक्ट को तामीर करेंगे। क्योंकि इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दुबारा लोड सेडिंग हो, दुबारा कारखाने बंद हों, मजदूर बेकार हों इससे मुल्क का ही नुकसान होगा। मैंने बंगाल की मिसाल दी। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसी जरूरत हर रियासतों की है सब की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, तवज्जह देने की जरूरत है।

मरकजी सरकार के मुलाजमतों में जो जगहें खाली होती हैं वे भरी नहीं जाती हैं, रिक्रूटमेंट के ऊपर बैन है और कम्प्यूटर बिठाकर और ज्यादा लोगों को बेकार बनाने का इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद यह दावा करते हैं कि बेकारी के मसले का हल कर देंगे। ये दोनों बातें मेल नहीं खा रही हैं। नेहरू रोजगार योजना का बड़े जोर से ऐलान किया प्रधान मंत्री जी ने। इस हाउस में हम लोगों ने सुना। ऐलानों की तो कोई कमी नहीं है। इसके पहले गरीबी हटाओ का ऐलान बहुत जोरशोर से हुआ। लेकिन इससे गरीबी कितनी हटी? मेरे ख्याल में अगर ये अपने दिलों को टटोलें तो उनको भी इसका जवाब मिल जायेगा। यही नहीं 20-सूत्री योजना, 15-सूत्री योजना, 5-सूत्री योजना, लोगों को याद भी नहीं है कि कितने ऐलान हुए। पिछले ऐलानों का जो हश्र हुआ वही हश्र इस का भी होगा। इसमें क्या कहा गया है इसमें कहा गया है कि हर ग्राम पंचायत को साल में 80 हजार से लेकर 1 लाख रुपया तक दिया जायगा। और उससे उस गांव के जो बेकार लोग हैं उनको 50 दिन से 100 दिन तक काम मिलेगा। क्या काम मिलेगा, कहां काम मिलेगा? फूड फार वर्क प्रोग्राम एक अच्छा प्रोग्राम चल रहा था। उससे गांवों के गरीबों को वाकई राहत मिल रही थी उसको बन्द कर दिया गया क्यों बन्द किया गया इसका कोई जवाब आज तक नहीं मिला है। यह जो कागज के ऊपर एलान हुआ है यह पैसा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा अगर पहुंचेगा तो कैसे खर्च होगा क्या काम उस गांव के लोग करेंगे यह किसी को मालूम नहीं है। मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हश्र दूसरे एलानात का हुआ है वही हश्र इसका भी होगा। जूट और कपड़े के कारखाने बन्द हो रहे हैं और सरकार सिंथेटिक की हौसलाअफजाई करके जूट की सन्नत को बरबाद कर रही है। हम लोगों ने कहा था कि जूट की सन्नत को तबाह करने के लिए सिंथेटिक को बाहर से मंगवाने के लिए अरबों रुपया खर्च करके ग्रेनूल्ज मंगवाये जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो 55 हजार करोड़ रुपये का कर्ज हिन्दुस्तान के ऊपर चढ़ गया है जिन महाजनों

[श्री मोहम्मद अमीन]

ने यह कर्ज दिया है जब हमारे मंत्री लोग वहां जाते हैं तो यह कहते हैं कि कर्ज हमने आपको इतना दिया है हम और भी कर्ज देंगे लेकिन कर्ज के साथ-साथ कुछ और भी देंगे और क्या देंगे जो हमारा रिजेक्टेड माल है वह आप हिन्दुस्तान में ले जाइये और पका जो बना हुआ माल है उसकी कीमत भी हम मुकर्रर करेंगे उसी कीमत पर आपको यह बेचना पड़ेगा । कर्ज के बन्धन में जकड़े हुए इन लोगों को यही डर है इसलिए महाजन जो कहता है उसको मान लेते हैं । इसका अंजाम यह होगा कि यह कर्ज कभी भी अदा नहीं होगा । यह हमारी सियासी आजादी के लिए भी खतरा पैदा कर देगा और यह हो भी रहा है । इसलिए इस एप्रोप्रियेशन बिल के ऊपर मुझे यह कहना है कि हकूमत ने अगर अपनी पालिसी पर नजरेसानी नहीं की तो कोई काम बनने वाला नहीं है । मुल्क के लोग बहुत दिनों से यह मांग कर रहे हैं कि बड़ी-बड़ी बातों को छोड़ कर जो छोटी-छोटी बातें हैं उन पर ध्यान दिया जाए । चावल, दाल, गेहूं, कोयला, कैरोसीन, खाने का तेल शक्कर, कपड़ा, साबुन, वगैरह जो जरूरी चीजें हैं जिनके बगैर इन्सान की जिन्दगी का एक दिन भी नहीं चल सकता है इन चीजों की कीमत मुकर्रर कर के कंट्रोल रेट पर मुल्क में सप्लाई करने का इन्तजाम किया जाए । यह कुछ ऐसा बहुत टेढा काम नहीं है इसमें कुछ दुश्वारियां भी होंगी लेकिन गवर्नमेंट अगर मंसूबा अपनाए तो इससे एक तो यह होगा कि चीजों के दाम बढ़ने से रुक जाएंगे दूसरा यह होगा कि जो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन मशीनरी बनाई जाएगी उससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन इससे कुछ लोग नाराज होंगे । कौन लोग नाराज होंगे वो लोग नाराज होंगे जिनके पास एक हजार, दो हजार, पांच हजार बीघा जमीन है, जो लोग अनाज पर बड़े-बड़े कादिर हैं, जो अवाम को भूखा मार कर दौलत के पहाड़ खड़ा करते हैं वो जमींदार महाजन लोग नाराज होंगे । उनकी नाराजगी की परवाह न करके हकूमत अगर आगे कदम बढ़ाए तो देश का भला हो सकता है लेकिन अब तक हम लोगों ने यही देखा है कि अपोजीशन के सामने हकूमत के पांव डगमगा जाते हैं इसलिए वह अपने इरादे तर्क कर देती है । जब आप इस तरह से हालात का सामना करने से कतरायेंगे तो कैसे कोई मसला हल होगा? यह कोई ऐसा काम नहीं है जो बहुत नामुमकिन हो लेकिन हो नहीं पाया है । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्ज में ज्यादातर नुकसान हो रहा है । क्यों नुकसान हो रहा है? क्योंकि इसको चलाने का तौर तरीका वही पुराना नौकरशाही का तरीका है । उन इदारों में काम करने वाले मजदूरों और मुलाजिमों को एहतमाद में नहीं लिया जाता है । वह लोग जो नुकसान दिखाते हैं उस पर तवज्जो नहीं दी जाती है । आपको एक मिशाल दे रहा हूं डिफेंस मिनिस्ट्री की । मैं भी दो दिन पहले जबलपुर गया था । जबलपुर में डिफेंस मिनिस्ट्री की एक व्हीकल्ज फैक्टरी है जिसमें गाड़ियां बनती हैं उसमें साढ़े ग्यारह हजार मजदूर काम करते हैं । उनकी मई दिवस के मौके पर तनख्वाह समेत छुट्टी मिलती थी । बहुत दिनों से मिलती आ रही है । मई दिवस मजदूरों का त्योहार है । इस साल मैनेजमेंट ने इसको कैंसिल कर दिया और कहा कि मई दिवस की छुट्टी अब नहीं मिलेगी । इस पर मजदूर बिगड़ गये और बिगड़ कर उन्होंने 28 मई को एक दिन की प्रोटेस्ट हड़ताल कर दी । इसमें कितने का नुकसान हुआ है । इस नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है । मजदूरों का जो अधिकार है अगर उसका आप एहतराम नहीं करेंगे तो वह मजदूर जी जान लगाकर मुल्क के लिए कभी काम नहीं करेगा । आप किसानों से, मजदूरों से और सरकारी कर्मचारियों से भी लापरवाही करते हैं तो फिर ख्याल किसका आप को है? ख्याल है टाटा, बिड़ला डालमिया, वालचन्द हीराचंद, सूरजमल, नागरमल, मफतलाल आदि का । इन्हीं लोगों का ख्याल है तो इनका ख्याल होने से जो अन्जाम होना चाहिए वही अन्जाम देश का हो रहा है । ये लोग उल्टे पनपते चले जा रहे हैं और मुल्क में आधी आबादी भूखी है । आधी

आबादी को पेट भर कर दो वक्त की रोटी नहीं मिलती है हालांकि प्रकृति ने हमारे देश को जो दिया है उसमें किसी चीज में कमी होने की बात नहीं है, यह बात हम सब लोग जानते हैं। इसलिए इन तमाम बातों को कहने का मेरा यही मकसद है कि हुकूमत मआशी मामलात पर नाकाम हो गयी है। यह कहना बहुत अच्छा नहीं लगेगा कि रिजाइन कर दीजिए आप, क्योंकि कहने से वे क्यों रिजाइन करने लगे। वे तो करेंगे नहीं। लेकिन यह बात जरूर है कि जो बातें मैं कह रहा हूं। ये बातें आज पूरा हिन्दुस्तान कह रहा है और ये अगर नहीं हटेंगे तो कल चुनाव में मुल्क के लोग इनको निकाल बाहर करेंगे इसमें कोई शक नहीं है।

SHRI BAUKUNTHA NATH SAHU (Orissa): Sir, I rise to support the Appropriation Bill. I will mainly speak on the subject of agriculture. Sir, the Ministry of Agriculture has not yet formulated a clear policy with a view to providing equal opportunities to the farmers. As you know, there are different kinds of land in our country There are irrigated and non-irrigated lands. In the irrigated lands, the farmers are getting minimum of two crops but in the non-irrigated lands, the farmers are able to raise only one crop. There are plains and there are highlands in the country. In the plains, the lands are more fertile than the highlands. It is seen that the Government is providing some facilities to the farmers, the marginal farmers and the small farmers in the areas where irrigation facilities are available, are able to derive double benefit in the matter of subsidy on seeds and fertilizers, whereas in the highlands where only single crop is grown, the farmer is able to derive the benefit of Government subsidy on seeds and fetilizers only once. So, my submission is that although we have to formulate a policy to provide equal opportunity to the agriculturists, in fact equal opportunity has not yet been provided to all the farmers, nor a clear policy has been formulated to provide equal opportunity to the farmers. The result is, the condition of farmers living in the high lands, where there is no irrigation facility provided, is not improving. Therefore, my submission is that where there are no irrigation facilities and where the farmers are getting only single benefit, they should be given double benefit and the same opportunity, the same benefit which is given to the agriculturists in the irrigated areas and it should also be given to the farmers cultivating in the highlands.

Another point is, a number of projects relating to Orissa are pending with the Central Government, awaiting clearance. As you know, in Orissa, the area under irrigation is very less in camparison with the other States. Therefore, I want that the projects pending with the Central Government should be cleared soon so that the economic standards of the farmers can be raised. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Mr. Yashwant Sinha. Five minutes.

SHRI YASHWANT SINHA: Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak.

Sir, the Budget exercise of the Government of India has been reduced to a farce for sometime now. But this year, it has assumed proportions which are ridiculous in the extreme. Before the ink dried on the Budget and while the Houses of Parliament are still in the process of discussing the Budget we come across a newsitem. I am quoting from the 'Economic Times' of 2nd May. It says in a headline that the Finance Ministry has issued instructions to all other Ministeries to cut expenditure in the current financial year, i.e., this year — for which we are discussing the Budget and the Appropriation Bill — by 5 per cent. Now, one fails to understand what is the kind of exercise in which the Government Indulges. This is an Appropriation Bill which has been passed by the Lok Sabha. It is now under the consideration of this House. In the meanwhile, we come across a newsitem of this kind.

[Shri Yashwant Sinha]

I would like to know from the hon. Minister whether the Ministry of Finance has, in fact, issued instructions that all the Ministries should reduce their expenditure by 5 per cent. If so, if the hon. Minister does confirm in this House that all the Ministries have been so instructed, I would most humbly submit, on behalf of the entire House, that, in that case, the Appropriation Bill which has been presented in this House should *suo motu* be reduced by 5 per cent. There is no reason for the Government to ask for a larger amount of money than what is warranted by its own instructions. Now, I am not talking of the pre-Budget levies. I am not talking of the levies which are imposed before the Budget, during the Budget and after the Budget. But here is a case which, as I said, beats all records. Even before the Budget is approved by Parliament in the Budget Session, the Ministry of Finance has been compelled to issue such an instruction. Before I come to the implications of this...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Has it come in the Press?

SHRI YASHWANT SINHA: I am quoting from the 'Economic Times'. It says 'Ministries told to save 5 per cent of their budgetary allocation'. Again, I am quoting from the 'Economic Times' of 1st May which says: 'Major import-intensive projects deferment likely'. What does this indicate? This is an indication of the severe foreign exchange crisis which the Government and the country are facing. This is an indication of the fact that Government might be compelled, because of the foreign exchange crisis, balance of payments crisis, to cut back on very important projects which have a large import content because the Government cannot afford it. I have started my submission in this House by Quoting from this news paper on these 2 major issues in order to point out that we do not seem to have any financial management worth the name, any budgetary management worth the name in this country. I am not talking of the increasing revenue expenditure, I am not talking of the huge budgetary deficit, huge trade deficits. I am not talking of the balance of payment problems that we face. I am not talking of enternal debt, of internal debt. I am not talking of self-reliance which we have thrown to the wind, which is one of the major legacies that we have inherited from the days of the freedom struggle. In the last four years I charge the Government having destroyed this one very important legacy of our freedom movement and something which we have practised for the last 38 years in this country. I am not talking of the Janata Government. I am talking of the policies which Shri Jawaharlal Nehru followed as Prime Minister of this country. I am talking of the policies which Mrs. Indira Gandhi followed. What has happened to those policies? I will just illustrate before I conclude my speech by mentioning only one thing and that is that we are all aware, you are particularly ware, that in this country we used to be very proud of the fact that we were as good managers as anybody else and that any technology transfer any investment would be seen, would be examined from the point of view of merits, from the point of view of suitability, from the point of view of need and this country has a record of having done with not only technology which we considered to be in appripriate but also of having rejected technologies and investments which we did not consider apropriate for this country. In no case in the history of independent India did this country depend on the management skills and the management expertise of freigners. We were very proud of the management skills of our own people. We have set up very large projects in this country. We have set up river valley projects, large steel

plants, large power plants. You are aware of them. In every case the ultimate responsibility for putting up those projects rested on Indian companies, on Indian expertise. Now what has happened? I am drawing the attention of this House with all seriousness in all humility but with all the emphasis at my command. In the last four years this country has gone in for turnkey projects, something which we did not countenance, something which was anathema for us. There have been projects where we have given the complete control, including the ultimate managerial control, to foreigners. They have been given on turnkey basis to foreigners. I am taking this opportunity not only to bring to the notice of the Government but to register my strong protest against his deviation from accepted national policies. The Government cannot so easily destroy the national consensus on issues which have been arrived at.

Now the Minister might be aware of the Chamera project. It is a hydro-electric project in Himachal Pradesh. What has happened in the case of the Chamera project? You have given almost a turnkey contract to a Canadian firm. What happened in the HBJ pipe line. You have given almost a turnkey project to a French firm. And these companies have not bothered to take to Indian consultancy. They have not bothered to utilise Indian equipment, Indian expertise that is available. Even I have dealt with areas where large projects were sanctioned. We used to analyse component by component, which are the areas where Indian technology was available, where Indian expertise, Indian equipment was available, where Indian manpower was available, and in no case was a foreign firm permitted to enter an area where Indian expertise, Indian equipment, Indian technology was available. In no case did we ever consider giving turnkey project, the overall management control to a foreign firm. Why have we departed from this? There is a hydro-electric project of Uri. There are various other projects in different parts of the country. We are considering for giving exactly the same kind of leeway to foreign firms. This is a major departure from the nationally accepted policy. I am not talking from the point of view of a narrow, partisan angle of a political party. I am talking from a nationalist point of view, I am talking from a point of view of national consensus on the basis of which this country has conducted its economic affairs in the last 40 years. Why should the Government give a go-by to those policies, to those programmes, to that ideology? This is what I demand to know from the Government through you, Sir, and I hope when the Minister gives his reply, he will be able to come clean on this and satisfy the House that there is no real departure. Thank you.

SHRI BASUDEB MOHAPATRA (Orissa): Sir, I rise to support the Appropriation (No. 2) Bill, 1989. Sir, we, the Members of the Treasury Benches, have no objection to the appropriation of the amount mentioned in the Bill.

This year's budget has highlighted the anti-poverty programmes as well as unemployment. In last year's budget importance was given to Kutir Jyoti, Jalandhar and Kisan Vikas Patrika schemes. Programmes like NREP and RLEGP would be under a single unit and the Centre is to give assistance up to 75 per cent, the rest to be borne by the State Government. This is a commendable step on the part of the Government.

Sir, last November, the All-India Congress Committee had passed a Resolution calling upon the Government to make a fresh evaluation of the various anti-poverty programmes meant for the rural poor. The AICC also gave a call for *Bekari hatao* along with *Garibi hatao*. Our beloved Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi, has already announced the Jawahar Rojgar Yojana, providing employ-

[Shri Basudeb Mohapatra]

ment to one member of each family below the poverty line. By this announcement, 4.40 crore families will be benefited. People living in the rural areas have welcomed this step taken by our beloved Prime Minister. I don't understand why our Opposition friends are criticizing this Jawahar Rojgar Yojana. They must understand that people living in the rural areas will be benefited by this and that they have already welcomed it.

Of course, with regard to the educated-unemployed, the problem is very serious. We see the vast number of unemployed youth knocking at the doors of the Employment Exchanges all over the country. If I am not mistaken, their number is about 30 million. Our Prime Minister is very particular about solving this problem, but the means are limited. Sir, in this context I would urge upon the Government to make a provision for a National Unemployment Allowance to the educated-unemployed youth in the country on the lines as in the UK and other foreign countries.

Sir, coming to this Bill, I may point out that under item No. 5, Department of Fertilizers, Rs. 1 crore have been charged under the Consolidated Fund of India. Here I would like to deal with fertilizers and say how the amount is being wasted. Each year, large sums are being given as subsidy on fertilizer. The amount is increasing year by year. During the last four years the amount paid as subsidy for indigenius production of fertilizers is as follows:

1985-86	...	Rs. 1,600 crores.
1986-87	...	Rs. 1,700 crores.
1987-88	...	Rs. 2,050 crores.
1988-89	...	Rs. 4,343 crores.

This year the subsiry is about 4.00 P.M. Rs. 5,173 crores. No doubt. this is a welcome step. But the farmers working in the fields, do not get any benefit. Half of the subsidy amount passes on to the mutinational company. This also has to be reviewed. The subsidy should be paid in such a way that the agriculturists working in the field should get the benefit.

Sir, in this connection, I would like to mention how the fertilizer plants in different parts of the country are making losses. In this regard I will not take much time. In Orissa, two fertilizer plants working in the public sector, are incurring heavy losses. The Talcher Fertilizer Plant of the Fertilizer Corporation of India has incurred a loss of Rs. 126 crores during the last four years. The Paradeep Phosphates Ltd. has incurred a loss of Rs. 30 crores during the last three years. This is the state of affairs of the fertilizer plants in my State. Efforts are not being taken to rectify the defects. On the other hand, the losses are mounting due to negligence of the officials. Even suggestions given by different firms to improve the condition of the fertilizer plants could not be implemented.

I would like to give one instance. In the case of the Talcher Fertilizer Plant, on the reommendation made by M/s. Krupp Koppers of West Germany, no action has been taken.

Sir, besides this, I would like to raise some important issues concerning my State of Orissa. In this House, I and my friends from Orissa have already asked to shift the Paradeep Phosphates Headquarters from New Delhi to Bhubaneshwar. This is a constant demand of the State of Orissa. Even the State Government is pressing hard to shift the office. But no action has been taken so far. The annual expenditure of the head office in New Delhi is bout Rs. 3 crores. This amount could have been saved if the head office had been shifted to Bhubaneshwar. When the head office of a public sector enterprise like the NALCO can function in Bhubaneshwar, it is not understood why the Paradeep Phosphates Ltd. authorities are hesitant to shift the office to Bhubaneshwar. Recenly, Sir, the matter was discussed on the floor of the

Orissa Legislative Assembly. After hearing the opinion of both sides in the Assembly, the Speaker directed the State Government to see that the head office be shifted immediately.

Sir, my second point regarding Orissa is that Orissa has got a vast coastal belt covering about 480 km. The State has abundance of marine fishing resources. During the Seventh Five-Year Plan emphasis was given to develop marine fish production to 1 lakh tonnes. The infrastructure facilities are available for construction of fishing harbours in the coastal belt of the State. The proposals for fishing harbour at Paradeep and Gopalpur are pending with the Central Government. The estimated amount for the Paradeep Fishing Harbour is about Rs. 23 crores and that for Gopalpur is about Rs. 8 crores. I request the Finance Minister that immediate steps be taken to clear these projects.

Sir, the proposal for an oil terminal in Orissa during 1989-90, is also pending with the Petroleum Ministry. The State Government has requested the Mnistry several times to establish the oil terminal at Paradeep due to erratic supply of petroleum products to the State. The neighbouring States have the facility for oil refining. So, their problem could be solved. We, the people of Orissa, have not demanded an oil refinery. We want an oil terminal alone. Orissa is not getting the supply of petroleum products regularly. So, the oil terminal should be constructed in Orissa immediately. My last point is that the drought situation in the State is very precarious. Rainfall was scanty in some parts of the State and the drought spell has already damaged the standing crop. The State Government has declared 4,007 villages as drought-affected in seven districts. These seven districts are Bolangir, Kalahandi, Cuttack, Ganjam, Sambalpur, Koraput and Phulbani. The worst affected districts are Bolangir and Kalahandi. Adequate Central assistance has not been provided to the State Government to meet the drought situation. I, through you, request the Finance Minister to provide adequate Central assistance so that the State Government will be able to meet the drought situation.

SHRI DARBARA SINGH (Punjab): One moment, Sir. I don't want to speak on the Appropriation Bill, but I would like to draw your attention to the fact that during the Budget debate there was a 'halla-gulla' from both sides and my speech was not heard. I had requested you to include it in the record. Anyhow it has not been done. Of course, I would like to know about all the appropriations that are being talked about here, but I would say that there is only one important thing that has to be done. That is the monitoring of our work on the ground that is being done, should be noticed and accountability should be there of every officer. Then whatever is being spoken on the Budget will certainly yield results.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Regarding your speech on that day I was told that your speech will be part of the report. I don't know what has happened to that. The Secretariat will find out and let me know about that.

श्री राम अवधेश सिंह : माननीय उप सभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया । मान्यवर, यह सरकार प्रति साल अपने बजट का घाटा बढ़ाती जा रही है और हर साल ऐसा वादा करती हैं कि अगले साल घाटा कम होगा, ऐसे कदम उठाए जाएंगे कि घाटा कम हो और देश में घाटे की अर्थव्यवस्था का जो कुपरिणाम निकलता हैं, वह नहीं निकलेगा ।

मान्यवर, आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी रहे हैं । आपको मालूम है कि घाटे की अर्थव्यवस्था का कितना कुपरिणाम निकलता है देश की अर्थव्यवस्था पर, गरीबों की जिन्दगी पर और मजदूरी करने वाले लोगों पर । यह सरकार हर बार घाटे का बजट पेश कर रही है और उसके कारण ऐसे बताती है जो आम आदमी

[उपसभाध्यक्ष (श्री बी० सत्यनारायण

[श्री राम अवधेश सिंह]

रेड्डी) पीठासीन हुए] की समय के बाहर की बात है । इस साल 7,940 करोड़ रुपए के घाटे का बजट है । पिछले साल 6,080 करोड़ रुपए के घाटे का बजट था । करीब दो हजार करोड़ रुपए इस साल बढ़ गए । यह सरकार का कहना है, लेकिन आपको मालूम है कि जो डेफिसिट फाइनेंसिंग में पैसे छापते हैं हम, उसका नतीजा उतने ही तक सीमित नहीं होता । 10 परसेंट अगर घाटे का बजट होगा तो कीमत बढ़ जाएगी कम से कम 20 फीसदी, ज्यादा भी बढ़ती है, 30 फीसदी भी बढ़ती है। दुनिया का कोई अर्थशास्त्री आकर बता दे कि विकासशील मुल्क में जब घाटे की अर्थव्यवस्था 10 फीसदी होगी तो असल बाजार में उसका असर कितना पड़ेगा। असल बाजार में उसका दाम 20 से 30 फीसदी बढ़ जाता है, जब मंत्रीजी जवाब देंगे तो कहेंगे कि हमने पूरी सावधानी बरती है, हम कोशिश कर रहे है कि कीमतें न बढ़ने पाएं पिछले साल भी आपने इस सदन में जब यह सवाल उठा था तो कहा था कि घाटे का बजट कम करो नहीं तो जितना प्रतिशत घाटे का बजट रखोगे उससे असली बाजार में कीमतें 30 प्रतिशत बढ़ जाएंगी । तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पिछले साल कितने घाटे का आपका बजट था और जो आप यह कह रहे थे कि दाम बढ़ने नहीं देंगे तो कितने प्रतिशत आम जिन्दगी में कीमतें बढ़ीं ? थोक बाजार में और खुदरा बजार में कितनी कीमतें बढ़ीं ? यह सब के अनुभव करने की चीज है ।

मान्यवर, जम्हूरियत में संसद सबसे बड़ा औजार है । यहां कुछ बोला जाए और सरकार कुछ ग्रहण न करे तो यह कोई अच्छी बात नहीं है । नहीं तो हम यहां बोले और सरकार अपने कान से निकाल दे तो उसका असर नहीं होता । मेरा सुझाव यह है कि घाटे की अर्थ-व्यवस्था के कई कारण हैं : उनमें से एक कारण तो यह है कि सरकार पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्ज पर, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के नाम पर लूटपाट बन्द करने में विफल रही हैं । उनमें इतनी लूट है सरकारी खजाने से हम पैसा लगाते हैं तो उससे हमको मुनाफा नहीं होता हैं बल्कि घाटा होता हैं । गांव में या कस्बे में यदि कोई एक लाख रुपया लगाकर कोई बिजिनेस करता है तो उसको भी साल में 10 से 15 हजार रुपए की आमदनी हो जाती है, प्राफिट होता है लेकिन हजारों करोड़ों रुपया सरकार जहां लगाती है उनमें 10 फीसदी मुनाफा नहीं मिलता है बल्कि हर साल 10 फीसदी घाटा होता है, नुकसान होता हैं । यह हमारे घाटे की अर्थव्यवस्था है ।

मान्यवर, मैं एक बहुत सनसनीखेज उद्घाटन यहां करना चाहता हूं और शर्म हो इस सरकार को और प्रेस वाले भी इस बात को गहराई से समझ लें कि यह राष्ट्रघाती बात हैं तो उसको पकड़ना चाहिए । लेकिन प्रेस वाले भी ऐसी बातों को नहीं पकड़ते जिससे सरकार हिले । यह बोफोर कांड से भी बड़ा भयानक होने वाला हैं । यह तय हो गय हैं कि स्टील माडर्नाइजेशन के नाम पर 15 हजार करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं और उन 15 हजार करोड़ रुपयों में जो भारत सरकार के हमारे उपक्रम हैं, जैसे मैकन हैं, वह ऐसा भारत सरकार का पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग हैं जिनके पास इतने सुसाधन हैं, इतने टैक्नीशियन हैं, इतनी नो-हाउ हैं, लेकिन जितने लोग यहां हैं उनकी राय लिए बिना, आर० एण्ड० डी० रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट शाखा से राय ली जाती है कि हम स्टील का डेवलप करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसका माडर्नाइजेशन करते हैं और इन सारी चीजों को करने के लिए भारत सरकार ने हजारों करोड़ों रुपया खर्च करके जो संस्थान बनाए, इस माडर्नाइजेशन की जो स्कीम बनाई जा रही है, उसमें जर्मनी, ब्रिटेन और जापान से कोलेबोरेशन करके, बिना इन संस्थाओं की राय लिए, 15 हजार करोड़ रुपया स्टील के माडर्नाइजेशन के लिए लिया गया है । इसमें दस फीसदी कमीशन ली गयी है ।

एक माननीय सदस्य : किसने लिया है यह भी बता दें ।

*Expunged as ordered by the Chair.

श्री राम अवधेश सिंह : यह लिखा है स्टील मंत्रालय ने ।* ...(व्यवधान)

ठाकुर जगतपाल सिंह (मध्य प्रदेश) : यह कौन से अखबार में आया है.... (व्यवधान)

श्री राम अवधेश सिंह : मैं कह रहा हूं इसकी जांच कराई जाए ।(व्यवधान)

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Yesterday, there was an order from the Chair that no allegation... (*Interruptions*)...It is ridiculous...

SHRI RAOOF VALIULLAH: This should be deleted from the record. (*Interruptions*)...He is speaking trash. (*Interruptions*)...

श्री राम अवधेश सिंह : मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं कि यह सनसनी खेज खबर है । इस बात के लिए एक कमेटी बहाल करिये । (व्यवधान) 15 हजार करोड़ की बात है । (व्यवधान) 15 हजार करोड़ की स्टील माडर्नाइजेशन की स्कीम क्यों लाई गयी ? आखिर वह किसके लिए बनायी गयी है ? (व्यवधान) हजारों करोड़ रुपया खर्च करते हैं (व्यवधान) । मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच कराई जाए । (व्यवधान) मैं ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूं । मैं कल सदन नहीं चलने दूंगा । मैं आज भी इस बात को कह रहा हूं, कि सरकार इस बात का जवाब दे । आज भी हम हाउस नहीं चलने देंगे । (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी) : समाप्त कीजिए ।

SHRI B. K. GADHVI: I am on a point of order. If the hon. Member wants to make certain allegations against any Member of this House or the Minister, then before he lodges such allegations, he has to give notice. Otherwise, he cannot make such baseless allegations. (*Interruptions*)...It cannot go on record.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI B. SATYANARAYAN REDDY): I will see (*Interruption*)...

श्री राम अवधेश सिंह : मैं यह कह रहा हूं कि अगर इस सरकार में दम है तो जो मैंने बात कही है उसकी जांच कराने के लिए वह कमेटी बहाल करे। (व्यवधान)

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : इन्होंने कहा कि मैं सदन नहीं चलने दूंगा तो सदन को यह चलायेंगे या आप चलायेंगे । (व्यवधान)

श्री रउफ वलीउल्लाह : अपनी पार्टी तो चलाइये । (व्यवधान)

श्री राम अवधेश सिंह : पार्टी चले या न चले लेकिन देश को लूटने की इजाजत नहीं देंगे । (व्यवधान)

[The Deputy Chairman in the Chair.]

THE DEPUTY CHAIRMAN: Just a minute. I did not hear. You know I was in my Chamber and I heard something. So, I want to find out what happened.

शांति के साथ बैठ जाइए और आप मुझे एक-एक करके बता दें कि क्या बात हुई । (व्यवधान)

Then I can give my ruling. I will listen to you. (*Interruptions*)

SHRI RAOOF VALIULLAH: The hon. Minister has already submitted. Why don't you say so?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, yes. Let the Minister speak.

SHRI B. K. GADHVI: While making a speech, the hon. Member referred to the modernisation of the steel plants. That was all right. But in his speech, he alleged** which should not go on record.

THE DEPUTY CHAIRMAN: About what he said?

SHRI B. K. GADHVI: He said, under the modernisation plan of the steel plants Rs. 15,000 crores are being used**

That cannot go on record because there is an accusation. (*Interruptions*)

**Expunged as ordered by the Chair.

श्री राम अवधेश सिंह : यह किसी की प्रोपर्टी नहीं है । **(व्यवधान)**

उपसभापति : अवधेश सिंह जी मैं आपका ध्यान...

श्री राम अवधेश सिंह : मेरी बात सुनी नहीं.

उपसभापति : मैं आपकी बात सुन रही थी तभी मैं आयी । मेरे कमरे में स्पीकर लगा हुआ है आपकी बात सुनी ।

श्री राम अवधेश सिंह : आपने अभी मंत्री जी से बात सुनी और मेरे लिए कह रहे हैं कि आपकी बात सुन लो । **(व्यवधान)**

उपसभापति : रूल 238-ए को आप पढ़ लीजिए । किताब नहीं है तो मैं आपको दे दूं ।

श्री राम अवधेश सिंह : इनको पढ़ना होता तो यह बोलते नहीं ।

उप सभापति : कोई भी चीज या किसी के ऊपर आपको एलीगेशन लगाना है तो उसके लिए आपको नोटिस देना पड़ता है । यह सदन कुछ कानूनों और कायदों के लिहाज से चलता है । इस तरीके से आप किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा सकते है । तो कृपया जो कुछ भी आपने कहा है या तो आप अपनी खुशी से उनको वापस कर लीजिये या आप नहीं करेंगे तो हम निकाल देंगे । आपका बड़प्पन इसी में है कि आप इस तरह की बात न कह कर खुद ही इसको विदड्रा कर लीजिये ।

श्री राम अवधेश सिंह : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है ।

उप सभापति : आपका पाइन्ट आफ आर्डर क्या होगा राम अवधेश सिंह जी, यह भी आपको सिखाना होगा कि मैं आपको कानून की बात बताऊं कि चेयर की रूलिंग के ऊपर कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठता है । अगर आप अपनी बात पर पाइन्ट आफ आर्डर उठा रहे हैं तो वह भी नहीं उठता ।

श्री राम अवधेश सिंह : : मैं आपसे सफाई चाहता हूं । जो लोग इस सदन में आकर अपनी बात कह सकते हैं, जो कुछ एलीगेशन लगाया जाय, कोई अभियोग लगाया जाय और जो लोग यहां सफाई दे सकते हैं, उनके बाबत ऐसी बात नहीं हो सकती है ।

(व्यवधान) मैंने रूलिंग नहीं दी है, रूल बताया है । कृपया रूल की किताब पढ़ लीजिये । उसके बाद आगे कुछ बोलिये । इसलिए आप अपने रूल मत बनाइये । जो रूल बने हुए हैं, पहले उनका पालन कीजिये । इसलिए आपने जो कुछ कहा है, आप खुद विदड्रा कर लीजिए, नहीं तो हम निकाल देंगे ।

श्री राम अवधेश सिंह : : महोदया, मेरा कहना है कि.... **(व्यवधान)** ।

SHRI RAOOF VALIULLAH: Madam, how can he continue to speak unless he withdraws it or you expunge it?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Anything said by him which is derogatory will be expunged. I will look into the records. If he does not withdraw anything which is derogatory, I will expunge it.

श्री राम अवधेश सिंह : आप मेरी बात तो सुनिये ।

उप सभापति : अब आपकी बात नहीं सुनेंगे ।

श्री राम अवधेश सिंह : ऐसा तानाशाही का काम मत कीजिये : आप मेरी बात सुनिये । सारी बात कैसे एक्सपंज हो जाएगी ।

उपसभापति : जो डेरोगेटरी बात है वह एक्सपंज हो जाएगी और जो आपने अच्छा भाषण किया है वह नहीं होगा ।

श्री राम अवधेश सिंह : ऐसा मत करिये, यह आप बुरी परम्परा मत चलाइये । मेरी सारी बात कैसे एक्सपंज हो जाएगी.... **(व्यवधान)**

डॉ० रत्नाकर पाण्डेय : हर बार माननीय सदस्य कहते हैं कि मैं सदन नहीं चलने दूंगा... (**व्यवधान**) अनुशासन-हीनता की भी एक सीमा होती है ।

उपसभापति : राम अवधेश जी, आपका समय खत्म हो गया है । आप यहां पर खड़े हुए हैं एप्रोप्रियेशन बिल पर बोलने के लिए । आप उसके बारे में बोलिए । आप इस तरह से बोलेंगे तो हंगामा होने ही वाला है । आप गलत बात करेंगे तो लोग भी चिल्लाएंगे ।

श्री राम अवधेश सिंह : महोदया, आप मेरी बात सुनिये ।

उपसभापति : आपका समय खत्म हो गया है ।

श्री राम अवधेश सिंह : ऐसी बात मत कीजिये, ऐसी जबर्दस्ती नहीं चलेगी । मैंने यह कहा है कि जो भारत सरकार की कम्पनियां थीं सलाह देने के लिए उनको मोडर्नाइजेशन के मामले में बाईपास करके हजारों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं । कोई मार्डनाइजेशन हो, विकास हो रिसर्च हो उस पर उसकी राय लेनी जरूरी है । लेकिन इसमें राय नहीं ली गई और 15 हजार करोड़ रुपये का सौदा विदेश से किया गया । इतना बड़ा सौदा करने के पीछे आखिर क्या बात हो सकती है और यह चर्चा है कि वहां... (**व्यवधान**)...

उपसभापति : ओ दुबारा न कहूं । आप इस विषय में कोई बात अब नहीं करेंगे । आप कृपया बैठ जाइये : आपका समय खत्म हो गया है । मैं दूसरे मेंबर को बुला रहा हूं ।

श्री राम अवधेश सिंह : मुझे आगे बोलने दीजिये ।

उपसभापति : नहीं, नहीं ।

श्री राम अवधेश सिंह : मैं दूसरे प्वाइंट पर बोलना चाहता हूं ।

उपसभापति : आपका समय खत्म हो गया है । श्री राम चन्द्र विकल ।

श्री राम अवधेश सिंह : कैसे खत्म हो गया ?

(**व्यवधान**)

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदया, मैं आपका आभार मानता हूं और विनियोग विधेयक ...(**व्यवधान**)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have called Mr. Ram Chandra Vikal. He is speaking. You please sit down, Mr. Ram Awadhesh Singh, Don't record anything of what he speaks now. I have called Mr. Vikal and he is speaking.

श्री राम चन्द्र विकल : माननीय उपसभापति महोदया, मैं आपका आभार मानता हूं ...(**व्यवधान**)

श्री राम अवधेश सिंह :*

उपसभापति : आप चुप रहिये बोलिये नहीं ।

श्री राम अवधेश सिंह :

उपसभापति : मैंने आपसे कह दिया है कि आपका समय खत्म हो गया । आपकी पार्टी के पास सिर्फ दो मिन्ट का समय था । आप बैठिये Nothing is being recorded of what you are saying.

श्री राम अवधेश सिंह : *

उपसभापति : चुप रहिये । विकल जी आप अपना भाषण कीजिये ।

श्री राम चन्द्र विकल : मैं विनियोग विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । (**व्यवधान**)...

(**इस समय माननीय सदस्य श्री राम अवधेश सिंह सदन छोड़कर चले गये**) ।

श्री राम चन्द्र विकल : महोदया, मैं आपका आभार मानता हूं जो आपने मुझे विनियोग विधेयक पर बोलने का मौका दिया ।

*Not recorded.

[श्री राम चन्द्र विकल]

महोदया, मैं इस विनियोग विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं प्रधान मंत्री जी की उन घोषणाओं का बहुत आदर करता हूं जो इन दिनों उन्होंने अल्प संख्यकों के लिये, महिलाओं के लिये आदिवासियों के लिये, जन-जातियों के लिये की है। पहली मई को उन्होंने मजदूरों की भागीदारी के संबंध में घोषणा की है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और आजकल की सामयिक समस्याओं से जुड़ी हुई है। मैं प्रधान मंत्री का इस मौके पर आभार मानता हूं जो उन्होंने मजदूरों की भागीदारी की घोषणा की। यह सवाल बहुत दिनों से चल रहा था और हमारे यहां अनेक बार ऐसे प्रस्ताव आये थे कि मजदूरों को भी भागीदार बनाया जाय। प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा से सारे देश के मजदूरों में एक खुशी की लहर दौड़ी है। इसी प्रकार महिलाओं के संबंध में जो उन्होंने घोषणा की है उससे आप भलीभांती परिचित हैं। यह घोषणा भी महत्वपूर्ण है। इसी तरह से अल्पसंख्यकों, जनजातियों और बैकवर्ड क्लास के लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिये प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है वे स्वागत योग्य है।

उपसभापति महोदया, मैं एक दो सुझाव देना चाहूंगा। पहला यह है कि शहर के नजदीक जो किसानों की जमीन है तो जो हमारे शहरों में विकास प्राधिकरण बने हुए हैं उनमें बड़ी तेजी से कंपीटिशन हो रहा है और वे किसानों की उपजाऊ जमीन को एक्वायर कर रहे हैं। उपसभापति महोदया, गवर्नमेंट का जी. ओ. है कि उपजाऊ जमीन कभी भी अधिग्रहित नहीं की जायेगी। ऐसा जी. ओ. केन्द्रीय सरकार का है। केबीनेट सेक्रेटरी का राज्य सरकारों को आदेश गया है लेकिन इस आदेश के बावजूद शहरों की नजदीक उपजाऊ जमीनों के अधिग्रहण किया जा रहा है। यह अधिग्रहण विकास प्राधिकरणों के नाम पर किया जा रहा है जैसे दिल्ली में डी.डी.ए. है गजियाबाद में जी०डी०ए० है इस तरह से दूसरे बड़े बड़े शहरों जैसे लखनऊ मेरठ देहरादून, हैदराबाद, कलकत्ता, भोपाल और नोएडा इत्यादि में जितने भी देश में बड़े बड़े शहरों में विकास प्राधिकरण है वहां की नजदीक जमीनों को विकास प्राधिकरणों के नाम से बेतहाशा ढंग से एक्वायर किया जा रहा है। किसानों की कोई सुनवाई नहीं होती है। दफा 17 लगा दी जाती है। हमारे यहां तो दफा 44 लगा दी जाती है विशेष पुलिस ले कर यह लोग आ जाते हैं। इन विकास प्राधिकरणों को पुलिस भी मिली हुई है ऐसा मालूम होता है कि न वह केन्द्रीय सरकार से माइंडेड होते हैं न राज्य सरकारों से। यह अकेली अपनी एक संस्था बन गये हैं जो अपने पास सारे अधिकार रखे हुए हैं, न जमीन का मुआवजा देते हैं और न वक्त पर मुआवजा देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के आदेश के बावजूद जमीन लेना सरकारी आज्ञा का तो उल्लंघन है ही लेकिन यह आर्थिक दृष्टि से भी ठीक नहीं है। एक तरफ हम इन्दिरा गांधी केनाल निकाल कर राजस्थान के सूखे और बीहड़ इलाकों में मंहगा पानी पहुंचा रहे हैं और दूसरी तरफ जहां केनाल बनी हुई है, ट्यूबवेल लगे हुए हैं, बाढ का पानी आता है, जमीन के अन्दर काफी मात्रा में पानी उपलब्ध है, अपने कुंए खोद कर भी हम सिंचाई की व्यवस्था करते हैं उस सिंचित जमीन पर आबादी बसाई जा रही है। उद्योगपतियों को भी जमीन बहुत तेजी से दी जा रही है। बड़े बड़े मुनाफाखोरों से अधिकारियों की भागीदारी इस में हम को दिखाई देती है कहां भी आप इसकी जांच करवा कर देख लें इस कार्य में अधिकारी भी लिप्त पाए जाएंगे। 10-10 करोड़ की जमीन उद्योगपतियों को दी जा रही है। चाहे उद्योग लगे या न लगे लेकिन थोड़े दिन के बाद लौट-फिर कर वह उस जमीन की भारी मुनाफे में बेच देते हैं। यही उनका सब से बड़ा उद्योग है। ऐसा एक कम्पीटीशन हो गया है। कुछ कालोनाइजर भी इस कम्पीटीशन में आ गये हैं। गवर्नमेंट से डरे हुए किसान कालोनाइजर्स को जमीन बेचने लगे हैं क्योंकि उनको डर है कि अगर एक्वायर होगी तो पता नहीं मुआवजा मिले या न मिले, मुआवजे के लिए रिश्वत देनी पड़ेगी और दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे लिहाजा कालोनाइजर्स और विकास प्राधिकरण कम्पीटीशन में हैं और उपजाऊ जमीन अधिक से अधिक घेरी जा रही है। यह तुरंत न रोका गया तो देश की पैदावार जो बढ़ी थी थोड़ी बहुत किसान ने हरित क्रान्ति और सफेद क्रांति जो लाई थी इस देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया था खाद्यान्न के

मामले में देश का भविष्य अन्धकारमय हो जाएगा। इसके बारे में शीघ्र समुचित कार्यवाही की जाए और केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को तुरंत आदेश दे। मैंने भी हर राज्य के मुख्य मंत्री को एक पत्र लिखा है। कृषि मन्त्री, उद्योग मन्त्री और शहरी विकास मन्त्री को भी पत्र लिखा है। मैं बराबर इसलिए लिख रहा हूं मुझे देश के किसान की चिन्ता है राष्ट्र की चिन्ता है। देश की जो पैदावार बढ़ी है वह एकदम निश्चत तौर से कम हो जाएगी। मैं एक दूसरा सुझाव देना चाहता हूं। पाकिस्तान में अभी नयी सरकार बनी है हमारे सम्बन्ध अच्छे हुए हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे प्रधान मन्त्री जी वहां गये बेनजीर भुट्टो के सन्देश भी बहुत अच्छे आए लेकिन यह समझ से बाहर है कि काश्मीर में ट्रेंड लोग पाकिस्तान से बहुत तेजी से आ रहे हैं। कुछ दिन पूर्व काश्मीर की आन्तरिक हालत इतनी भयावह हो गई है कि अगर हमारी होम मिनिस्ट्री, काश्मीर गवर्नमेंट जिसमें हमारी पार्टी की सांझेदारी है और हमारे रक्षा मन्त्रालय सजग न हुए तो काश्मीर में खतरा कुछ बढ़ सकता है और इतना भंयकर बढ़ सकता है जिसका आज आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। बहुत शोचनीय स्थिति है इस पर तुरंत कोई कार्यवाही आपको करनी चाहिये। पाकिस्तान से आतंकवादी कहिये, मुजाहिद कहिये, ट्रेनिंग लेकर आए हैं और बम फट जाते हैं दुर्घटनाएं भी हो रही हैं (व्यवधान)

उपसभापति : आतंकवादी का अनुवाद उर्दू में मुजाहिद नहीं होता है। मुजाहिद वह होता है जो दूसरों को आजादी के लिए लड़ता है।

श्री राम चन्द्र विकल : वह तो मुजाहिद बन कर आते हैं। यहां वाले लोगों को वह गुलाम कहते हैं। यह मुजाहिद सन् 1947 से आ रहे हैं पाकिस्तान से। मेरी जानकारी है यह मुजाहिद बन कर आ रहे हैं वह अपने को मुजाहिद कहते हैं और यह कहते हैं कि हम तुम्हें आजाद कराएंगे तुम गुलाम हो। यह ट्रेनिंग लेकर आते हैं मैं सन् 1947 से जानता हूं। 1965 के युद्ध में मुजाहिद बन कर आए कहते हैं कि तुम गुलाम हो हम तुम्हें आजाद कराएंगे। बहुत घटनाएं उनकी मैं जानता हूं। वे अपने को मुजाहिद और यहां के लोगों को गुलाम कहते हैं। सही हो गया कि नहीं उपसभापति महोदया ?

उपसभापति : आप सही हैं वे गलत हैं।

श्री राम चन्द्र विकल : वे गलत हैं मगर मुजाहिद का नारा देकर वे आते हैं। खैर, मैं काश्मीर की चिंता इसलिए व्यक्त कर रहा हूं कि हालत वहां की कुछ अच्छी नहीं है। अपनी गवर्नमेंट को, केन्द्रीय सरकार को, होम मिनिस्ट्री को, रक्षा मन्त्रालय को और काश्मीर गवर्नमेंट को भी इसमें तात्कालिक कोई उपाय करने चाहिए। साथ ही मैं जनता से इस मौके पर अपील करना चाहता हूं चाहे वह काश्मीर की जनता हो चाहे अपने देश की।

महोदया, साम्प्रदायिकता पर 2-3 दिन से बहस हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सारा सदन इस देश की साम्प्रदायिकता से चिंतित है चाहे वह धार्मिक साम्प्रदायिकता हो चाहे आर्थिक हो या और किसी तरह की हो चाहे जातीय हो। यह हमारे देश के लिए एक अभिशाप है और खतरा है। आजादी के वक्त तो बड़ी मुश्किल से हम लोग इकटठे होकर इस मुल्क को आजाद करा सके थे मगर आज की साम्प्रदायिकता बड़ी विषैली हो गयी है चाहे वह वोट की खातिर हो चाहे वोट की खातिर। इस साम्प्रदायिकता के खतरे से मुल्क को यूं बचाना पड़ेगा कि अगर हमारे यहां किसी तरह के देश के अंदर झगड़े होते हैं तो हमारी सेना एवं जो सीमाओं के लिए हैं उनको यहां लगाना पड़ेगा, जो देश के लिए बहुत भारी खतरा हो सकता है। आज जो बाहरी चुनौतियां हमारे देश में हैं, अन्दर और बाहर से, उनमें सीमाओं का खतरा इतना नहीं है जितना कि अन्दर की साम्प्रदायिकता का खतरा है। इससे भी हमें राजनीतिक तौर से और धार्मिक गुरूओं से अपील करके, जनता से अपील करके देश को बचाना है। सबसे पहले साम्प्रदायिकता के खतरे में भाईचारे और आपसी मेल-मिलाप से इसको समझकर एक होना है, वरना यह न हो जाये कि साम्प्रदायिक दंगे इतने भयावह हो जायें और जिसकी आशंकाएं हैं चूंकि बाहर की जो साजिश है वह ज्यादातर यह है कि विभिन्न

[श्री राम चन्द्र विकल]

रूप से हम यहां की जनता को धर्म, जातियों, क्षेत्रों आदि अनेकों नामों से भड़काकर देश में आग लगायें ताकि बाहर के लोगों की मंशा पूरी हो। अतः इस विनियोग विधेयक के अवसर पर मैं देश की जनता से, सभी धर्म गुरूओं से, जातियों से और पार्टियों से अपील करना चाहता हूं कि राष्ट्र सर्वोपरि है। इस राष्ट्र की एकता और अखंडता पर हमें अपनी पार्टियों को बार देना चाहिए, हमें अपने धर्मों को राष्ट्र के लिए समर्पित कर देना चाहिए और जातीय विद्वेष कहीं हैं तो उनको भी राष्ट्र को समर्पित कर देना चाहिए। मैं अपील करते हुए यह आशा करूंगा कि हमारे देश के अंदर के खतरे में हम आपस में एक हो जायें तो बाहरी खतरा कभी हमारे देश का कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विनियोग विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे किसानों की समस्याओं को हमारी आर्थिक समस्याओं को और हमारी जो साम्प्रदायिक समस्या हैं इनको हम और आप और जनता सब, विरोधी दल भी दूर करेंगे, इसमें भागीदार होंगे और देश की एकता और अखंडता पर खतरे की चुनौती का सब मिलकर सामना करेंगे। मैं आपका आभारी हूँ।

उपसभापति : आतंकवाद का उर्दू वर्ड नफरीबकार है। जो डिस्ट्रक्शन करता है, जो तोड़फोड़ करता है।

श्री राम चन्द्र विकल : वह आपकी तरफ से जुड़ जायेगा, मुझे कोई एतराज नहीं है।

उपसभापति : मुजाहिद जो होता है वह अच्छे काम के लिए लड़ता है।

श्री राम चन्द्र विकल : वे अच्छा ही बताते हैं।

उपसभापति : वे गलत बताते हैं।

SHRI PUTTAPAGA RADHAKRISHNA (Andhra Pradesh): Thank you, Madam. Madam, we had a sufficient debate on the Budget and we have discussed the Appropriation (Vote on Account) Bill and the Appropriation Bill also. This is the second Appropriation Bill. We will discuss it and it will ultimately be returned. There is no problem. But on this occasion I want to make some comments.

Madam, while speaking on the Appropriation (Vote on Accounts) Bill on the 29th March this year, I had mentioned one thing that this Budget was the result of a confusion in the mind of the Government. They have tried to make it an election budget, but it could not take a complete election shape. I had mentioned one thing. I had mentioned that the Finance Minister has come down heavily on essential commodities for the middle class, like TVs, radios, two-in-ones, pan masalas and all that. I requested the Finance Minister to withdraw those duties, since they are consumer goods for the middle class people. Afterwards, the Minister has conceded the demand. I think, the Minister has withdrawn those duties and he has given the concession not because of the demand of the Opposition Members, but he has done it keeping in view the forthcoming elections. Madam, everything is publicity-oriented here. This is one instance of it. Afterwards, this Jawahar Rozgar Yojana is there. It is more publicity-oriented than welfare-oriented. Madam, we have no objection for the Jawahar Rozgar Yojana. We want more funds for this Yojana, and we want to help the poor people and the unemployed youth as the Government claims. But there is one objection. Recently the Government have been talking of direct finances to the *panchayats* at the village level for this scheme. It is objectionable because whatever funds may come from the Centre, they have to go to the State Government, and the State Government has to allocate the funds to the districts and the other units in the State, and the execution is to be overseen by the State Government. Here, it

seems, the Government of India is undermining the very existence of the States. Madam, it is not only that but it is also an unconstitutional interference in the functioning of the State Governments. It seems the Government of India do not want to recognise the existence of the States. They want to convert the entire States into Union Territories, they want to takeover the entire administration of the State Governments. It is not justified as per the Constitutional provisions as also morally.

Madam, recently, the Government of India, particularly the Prime Minister has started a proposal about Amendment to the Constitution to strengthen the Panchayati raj institutions. Madam, we have no objection for an Amendment to the Constitution to strengthen the Panchayati raj institutions. We will support it. But this must be within the ambit of the State Government. It is a State subject, and the Government of India cannot take-over it and they cannot bypass the State Governments. That is our objection. Madam, on this occasion, I would like to mention one thing. Recently, the Prime Minister has gone to Bangalore after the dismissal of the State Government there to address some Panchayati raj convention...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Prime Minister did not discuss it at all...

SHRI PUTTAPAGA RADHAKRISHNA: If the Prime Minister disowns the action, it is all right. Madam, the Prime Minister has mentioned at Bangalore that the Panchayati raj setup in Andhra Pradesh is weak and it has not developed. He has passed some remarks on this occasion. I would like to tell something...

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): I saw that programme on TV. Prime Minister said that we have to learn lessons from various places.

SHRI PUTTAPAGA RADHAKRISHNA: He has mentioned Andhra Pradesh. He has given some instances. I will explain that in detail. Madam, the Prime Minister has mentioned about the constitution of development and review councils for the Districts in Andhra Pradesh. The Prime Minister also mentioned about the suspension of ten Presidents of the Panchayat Mandals in Andhra Pradesh. Specifically, he has mentioned Andhra Pradesh. He has spoken about the non-effective functioning of the Panchayati raj institutions in Andhra Pradesh. Madam, in fact, the Panchayati raj set-up is strengthened in Andhra Pradesh after the Telugu Desam has takenover the Government there. Madam, previously, there were about 320 Panchayat Samitis in Andhra Pradesh After the taking-over by the Telugu Desam, 1092 Mandal Praja Parishads are functioning there. Madam, the Chairman of the Zilla Praja Parishad is given the status of a Minister of the State. And, apart from that there are some powers additionally given to Zila Parishads and other Panchayati Raj institutions. Earlier before this budget came into force there were two schemes meant for rural areas, i.e., NREP and RLEGP. For these the funds are provided by the Government of India. According to the Government of India guidelines they are to be administered and supervised by the DRDA, i.e. District Rural Development Agency. In our State, the Government of Andhra Pradesh has entrusted that job to Zila Praja Parishads. Apart from that the functioning of Zila Praja Parishads is different from the development and review committees. The Prime Minister has mistaken these things. The development and review committees are constituted with the MPs and MLAs of the district presided over by a Minister. The Prime Minister has mentioned that the powers of the Zila Praja Parishad are given to the Minister concerned who presides over the council. That is wrong.

[Shri Puttapaga Radhakrishna]

The Minister who presides over the Council has no specific power at all. This is only a reviewing body. It will have a review over the administration of the district. It is not confined to panchayati raj institutions alone. Panchayati raj institutions are quite independent and they manage their funds and powers themselves. The council has nothing to do with the interference of local bodies. The Prime Minister has gone to the extent of mentioning the suspension of ten presidents of mandal praja parishads.

Madam, as I have mentioned earlier there are 1092 mandals functioning in the State. According to the Act if any panchayat mandal president violates the Act or the rules made thereunder, he can be suspended or removed. Out of 1092 mandal presidents, the Government of Andhra Pradesh has suspended, not dismissed, only ten MPP presidents, including some Telugu Desam Presidents. Here it is clear that the Government is fair enough and they are functioning according to the Act provided for that. Is it worse than dismissing the State Governments—suspension of mandal praja parishads? It is not worse than dismissing the State Governments. They have gone to a court of law. They have obtained stay orders and they are continuing. Here we have seen the recent case of Karnataka, the State Assembly was dissolved, the State Government was dismissed. There is no remedy for reinstatement or continuance of the Government. But that is not the case in Andhra Pradesh. (*Interruptions*). The court cannot give the stay orders now and the Government cannot be reinstated. (*Interruptions*). That is the independence of legislatures, Madam. It is not the problem of Andhra Pradesh legislature alone. The matter that you are mentioning does not concern only the Andhra Pradesh legislature. It is the basic question of the supremacy of legislature, independence of legislature. It may be legislative assembly or a House of Parliament. It is a question to be decided.

Madam, the State Government has given much effect to the provisions of this Act and they have improved the functioning of the Panchayati Raj institutions. Apart from that the Treasury Benches are very much claiming and they are very much talking about reservations to women. In our set up the Andhra Pradesh legislative assembly has passed a resolution providing 30 per cent reservation to women in Government jobs a long time ago, some five years ago or so, for the first time in the country. (*Interruptions*). If you talk of some nasty things I can also speak. Madam, the Government of Andhra Pradesh has provided for 30 per cent reservation to women. We have also created political reservations for women in the panchayati raj set up in the Zila Praja Parishad and Mandal Praja Parishad. We have provided 9 per cent reservation for women and some seats are also reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and backward classes. That is why, the Government of Andhra Pradesh has taken steps to strengthen the functioning of the panchayati raj institution and panchayati raj set up now in the State is stronger than the set up that existed before the Telugu Desam Government took over. Madam, the Government here is very fond of publicity out of these things instead of initiating some welfare of developmental measures.

With these comments, I conclude. Thank you.

श्री हरि सिंह (उत्तर प्रदेश) : माननीय डिप्टी चेयरमैन महोदया, मैं एप्रोप्रिएशन (नंबर 2) बिल, 1989 के समर्थन हेतु खड़ा हुआ हूं और उसकी सफलता के लिए मैं समर्थन करता हूं। यह बड़ी खुशी की बात है कि हमारी सरकार ने जो डेमोक्रेसी की नींव है, उस डेमोक्रेसी की नींव को मजबूत, सुदृढ़ और विकसित करने के लिए, उनको आर्थिक और विकास की जिम्मेदारी सौंपने के लिए, जो नीति और कार्यक्रम बनाए

हैं, वह प्रशंसनीय हैं । इससे न केवल प्रशासनिक बल्कि जो साधारण से साधारण आदमी गांव में रहता है जो अनपढ़ है, जो मूल समस्याओं को जानता है कि ग्राम के विकास के लिए किस बात की आवश्यकता है, उसके विकास को बढ़ाने के लिए किस बात की जरूरत पहले है, इन सबको देखने के लिए कोशिश की गई है और यह ग्राम पंचायत और ग्राम से लेकर जिले तक जो विकास की धुरी है, वह नागरिकों के हाथ में दी जा रही है । यह अपने आप में एक बड़ा अनोखा और क्रांतिकारी कदम है ।

इसके साथ साथ महोदया, यह नेहरू रोजगार योजना है । जैसा आप जानते हैं देशों में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है और केन्द्र सरकार बराबर इस बेरोजगारी को खतम करने के लिए एक नहीं, एक के बाद एक कदम उठाती जा रही है और उनमें एक यह कदम बड़ा क्रांतिकारी है । यह इस मायने से कि इस योजना के मसहत लाख नवयुवकों को रोजगार मिलेगा और हर परिवार के एक आदमी को रोजगार मिलेगा । इसलिए यह जो एक बहुत बड़ी योजना बनाई गई है, यह प्रशंसनीय है ।

महोदया, जैसा मैं कह रहा था कि हमारी सरकार का बराबर यह प्रयत्न है कि हमारे देश में जो गरीबी है, बेरोजगारी है, आर्थिक असमानता है या अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरे देशों पर कुछ चीजों के लिए निर्भर रहने का है, इनको खतम करना है और इनको खतम करने के लिए हमारी योजनाओं के जरिए, हमारे बजट के जरिए सरकार द्वारा प्रयत्न किए जा रहे हैं । आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है, मजबूत है और वह अपने पांव पर खड़ा हुआ है। आज भी हमारे पड़ौसी मुल्क, नाम मैं नहीं लेना चाहता, आज भी वह हर चीज के लिए विदेशों की तरफ देखते हैं, लेकिन यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारा देश छोटी से छोटी चीज से लेक बड़ी से बड़ी चीज तक अपने देश में पैदा करता है, मैन्यूफेक्चर करता है । हमारे देश में कई ऐसी चीजें भी मेन्युफेक्चर की जाती हैं, जिनसे एक नहीं, करोड़ों रुपए की फोरेन-एक्सचेंज हमारी बच जाती है ।

आर्थिक तौर पर जो हमारा हिंदुस्तान है, यह केन्द्रीय सरकार की योजनाओं के जरिए, बजट को अच्छी तरह बनाने, चलाने के लिए जिन बातों की आवश्यकता है, उनको नजर में रखने के कारण ही सुदृढ़ हुआ है, मजबूत हुआ है और इसकी बुनियाद जो है वह बहुत गहरी हुई है । अब अगर कोई आंधी के झकझोड़े पड़े या थपेड़े पड़े, तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारा आर्थिक ढांचा, हमारी बुनियाद जो आर्थिक तरक्की की है, यह कभी ढीली या कमजोर होने वाली नहीं है । इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं ।

महोदया, जैसा आप जानती हैं कि हमारा देश खेतिहर है । अगर देश का किसान मालदार होगा । तो देश मालदार होगा और देश का मजदूर अगर खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा । केन्द्र सरकार की इन सारी योजनाओं के जरिए आज आप देखेंगे तो हमारे गांव की सूरत बदलती चली जा रही है एक वक्त था जब गांव के अंदर साइकल नहीं दिखाई देती थी, आज लड़के-नौजवान मोटर-साइकिल लिए चले जाते हैं एक-एक गांव में बीस-बीस, तीस-तीस, चालीस-चालीस, पचास-पचास ट्रैक्टर्स दिखायी देते हैं और मालूम पड़ता है कि साइकिल का युग खत्म हो गया है । जीप और ट्रैक्टर्स का युग आ गया है । आज हम देखते हैं कि जिन गांवों में अंधेरा रहता था वहां बिजली की भरमार है । यह इसलिए हो सका कि हमने अधिक बिजली उत्पादन किया । कैसे किया ? पैसे से की क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई । हमने "नो हाऊ" भी सीरक और अपना भी

[श्री हरि सिंह]

डवलप किया । हमारे इंजीनियर्स ने प्लानिंग को, डिजायनिंग को डवलप कर के देश को तरक्की दी है । मैं विदेश नीति के बारे में नहीं कहना चाहता । खेती के बारे में आप देखें जहां पहले हम बाहर से अन्न मंगाते थे आज दूसरे देशों को भेजते हैं । आज हमारा किसान प्रोग्रेसिव किसान है । आज का किसान प्रेमचंद के "गोदान" वाला किसान नहीं है । आज कोई साहूकार उसे सता नहीं सकता, तंग नहीं कर सकता, उससे बेगार नहीं ले सकता, उसपर जुर्म नहीं कर सकता । अंग्रेजों के जमाने में इस प्रेमचंद के उपन्यास "गोदान" ने क्रांति कर दी थी । अंग्रेजों ने उसपर पाबंदी लगा दी थी, यदि प्रेमचंद के गोदान वाले किसान को हम आज राजीव के किसान से मिलाकर देखें तो उसमें जमीन-आसमान का अंतर है । यह कम क्रांतिकारी कदम नहीं है । आज आर्थिक दृष्टि से देश मजबूत होता चला जा रहा है । लेकिन किसान की तरक्की के लिए मेरा एक सजेशन है कि उसको एक नहीं मल्टीफेरस एक्टिविटीज में लगना होगा । आज किसान की ऋण-मुक्ति के लिए अनेक स्कीम्स हैं उसके लिए बैंक्स की स्कीम हैं । ट्रैक्टर्स, ट्यूबवैल, बिजली और सिंचाई के लिए स्कीम्स हैं । छोटे-छोटे उद्योग-धंधे चलाने केलिए बहुत सारी स्कीम्स हैं । आज जरूरत इस बात की है कि हमारा किसान जापान के किसान की तरह से हो जाय । ऐसी परम्परा डाली जानी चाहिए । उसे अपनी मनोवृत्ति को थोड़ा-सा बदलना होगा । उसे खेती के साथ मछली पालन और मक्खन व दूध का उत्पादन भी करना चाहिए । उसे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है । यह मक्खन बनाए । खेती के काम के साथ गाय का काम भी करे । इस तरह वह किसी पूंजीपति से कम न रहे । यही हमारी सरकार की नीति है ।

महोदया, आप इंडस्ट्री की पॉलिसी को देखिए । इंडस्ट्री के लिहाज से हमारा देश कितना मजबूत हुआ है ? आज हमारे यहां बड़े-बड़े कारखाने हैं । आज एटोमिक से लेकर दुनियाभर के बड़े-बड़े कारखाने देश में खड़े कर हम अनेक क्षेत्रों में हम मुल्क की तरक्की के लिए प्रयास कर रहे हैं । उसे मजबूत बना रहे हैं । फर्टिलायजर की बात की जाती है । जहां पहले फर्टिलायजर का पांच किलो का औसत था, वहां आज औसत कितना बढ़ गया है ? वह कितने फर्टिलायजर का इस्तेमाल कर रहा है । यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हमने अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की है । हम अपने पैरों पर खड़े हुए हैं । हम आर्थिक तौर पर स्वावलंबी हुए हैं । अभी लोग कह रहे थे कि हम विदेशी कर्जे से लदे हैं । विदेशी कर्ज क्यों लिया गया ? देश की तरक्की के लिए, विकास के लिए । आज दुनिया का कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो किसी-न-किसी रूप में चाहे कामेडिटीज हो या रुपया-पैसा हो, विदेशों से उधार न लेता हो । यह तो डिप्लोमेसी और एक्स्टर्नल एफेअर्स के रिलेशंस का पार्ट है । आज चीन रूस से कर्ज ले रहा है और अमेरिका चीन से ले रहा है । दोनों की आयडियोलोजी में, ख्याल में, प्रशासन में अंतर है लेकिन वे आर्थिक तौर पर चीजों का आदान-प्रदान कर रहे हैं ।

महोदया, आज देश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है । आज गांवों में सड़कें बनायी गयी हैं । यह सब इस बात का द्योतक है कि हमें स्वतंत्रता दिलानेवाले जो हमारे नेता थे—गांधी जी, जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी, इन सब ने हमारे विकास की योजनाओं की जो नींव रखी, उसके लिए जो प्रायरिटीज तय की उसी पर चलकर आज हमारा देश दुनिया के मुल्कों से आगे है । आज हमारे पास शक्ति है, लीडरशिप है । हम देखते हैं कि दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में आज कितना खून-खराबा हो रहा है, आंदोलन हो रहे हैं, हिंसा का राज कायम हो रहा है । लेकिन यहां डेमोक्रेसी में हमारा यकीन है और उसे मजबूत बनाया जा रहा है । इसमें जनता को भागीदार बनाया जा रहा है । यह कम गौरव की बात नहीं है । अभी एक सदस्य कह रहे थे कि ग्राम पंचायतों का जो पंचायती राज स्थापित किया जा रहा है इससे स्टेट्स का हक छीना जा रहा है, उनकी स्वतंत्रता

छीनी जा रही है, उनके काम करने के तरीके में दखल दिया जा रहा है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज सत्ता का, पावर का जितना डिसेंट्रलायजेशन होगा उतना ही देश मजबूत बनेगा । इस का सारी पार्टीज के लोगों को स्वागत करना चाहिए । मुझे आशा है कि गांव और शहर सभी लोग इसका स्वागत करेंगे ।

इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इस एप्रोप्रिएशन बिल का समर्थन करता हूं धन्यवाद ।

5.00 P.

*SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN (Tamil Nadu): Madam Deputy Chairman, I rise to speak on the Appropriation Bill (No. 2) 1989 on behalf of D. M. K. This Council of States is regarded as the 'House of elders' having scholars and experts in diverse fields as its Hon. Members. Our late lamented leader Dr. Anna was a Member of this august House long time ago. While I deem it a matter of great privilege and pride to be a Member of this House, I feel it is my bounden duty to record my thanks to Dr. Kulaingnar, my reverend leader and the Chief Minister of Tamilnadu, for having sent me here. I have decided to make my maiden speech in my mother tongue, Tamil. I know for certain that the Hon. Members sitting here listen to my speech with all eagerness and enthusiasm. But I am aware that most of you sitting here can not understand Tamil. So also, when Hindi is spoken, we do not understand. But we sit together and work in this House because ours is a unique nation where we have unity in diversity.

I know if I speak in English you can hear me direct and understand better. I also know there are Hon. Members who would love to listen to me speaking in Tamil. But I have a grievance, a very genuine grievance. Though I have the right to speak in Tamil in this House, what I say in Tamil is not recorded in Tamil in the official Report. Speeches are being recorded in English, Hindi and Urdu. But Tamil does not find a place in this select band of privileged languages. So, it is my desire that speeches made in Tamil should be recorded in Tamil. I hope the Hon. Members sitting here will appreciate me and extend support to what I say.

This Appropriation Bill, which is a ritual exercise is nothing but a jugglery of figures, a bewildering list of titles and sub-titles with boggling statistics. The common benefit of this is only confusion. I say so with a sense of responsibility. For example you have levied 8 per cent surcharge on Income-tax. This surcharge goes to the centre in In spite of levying surcharge, had the Centre increased the Income-tax itself, the State Governments would have been benefited. You quite often forget that the States are the vital organs that make this country. Whenever you formulate a policy, you have the non-Congress (I) Governments in mind and therefore your policies are sodden with malice towards the States. But what is the result? The Congress ruled States also suffer. So I appeal to your good sense not to treat the State Governments as your rivals.

It is very painful to note that this 8 per cent surcharge is levied despite the recommendation of the Seventh Finance Commission not to charge any surcharge. Secondly, in the current year budget, under Revenue account Rs. 2,300 crores have been credited against oil pool account. Because of this crediting you could present a low-deficit budget. But I remind you that the oil pool account money is not something to be utilised by the Union Government alone unilaterally. To buffer the price fluctuations of oil and petrol in world market, we have this oil pool account. So, it should not be misutilised this way. Again, when the centre gets profit by increasing

*English translation of the original speech delivered in Tamil.

[Shri Pashumpon Tha Kiruttinan]

the oil price, it pockets the entire profit without giving the States their due share. This is highly irregular and amounts to betrayal.

Now I come to excise duty. On very many occasions this excise duty on certain items is either abolished or reduced without consulting the State Governments. I would like to say very assertively that in a federal State like India it is incumbent on the Union Government to consult the State Governments before taking any such decision. I say so emphatically because the State Governments have the right of share in the excise duty. This only highlights the high-handed ness of the Centre. However, I wish to go on record to say that I am not against abolition or reduction of excise duty. Indeed I welcome such decisions. But, it pains to note that the concession on excise duty have been extended only to large scale industries. The needy cottage and small scale industries have not been given this benefit of concession. I will give just one example. Concession to the tune of about Rs. 11 crores has been extended to the match industries. This concession has benefited only the large scale industries like VIMCO match industries. Thousands of cottage match works located at Saatur, Sivakasi, Kovilpatti, Thirumangalam, Gudiyatham and Thirunelveli in Tamilnadu and such industries all over the country have not got the concession. It is a matter of serious concern that merits an honest review of the policy at the earliest. It is startling to compare the excise duty levied on mechanized industries like VIMCO by the Janata Government in 1979 and by the Congress Government today. The concession given on 5-gross bundle of match box manufactured by large scale industries is Rs. 23.50 as against a meagre Rs. 2.50 on the same 5-gross bundle manufactured by the cottage industries. On the other hand you have increased the excise duty on potassium chloride a raw material required by the match industries. The increase in excise duty on certain amount of potassium Chloride required for making 5 gross match boxes is Rs. 3.00. On one hand you have given a paltry concession of Rs. 2.50, on the other hand you have increased the excise duty by Rs. 3.00. Then where is the concession to cottage industries? I wish to ask whether your concession to large scale indutries have gone down to the consumers as you often claim? On the contrary, while a match box manufactured by the large scale industries like VIMCO is sold at 30 paise, the one manufaetured by the cottage industries is sold at 20 paise. The large scale industries have not reduced the price at all. This concession has gone only to the advantage of industrialists and middlemen.

Madam, every year, before preparing the budget, the Union Government goes through a ritual known as pre-budget discussion. In this discussion even Chief Ministers are invited. I say it is ritual because, regardless of the deliberation there, you increase the prices of the essential commodities arbitrarily. Yet again, you increase the administrative prices of those commodities. The ultimate burden is passed on to the feeble shoulders of the common man. To top it all, the revenue netted this way is pocketted by the Centre alone. You are very clever. Because, if you have to collect this revenue by way of tax rather than increasing the price, you will have to share such revenue with the States. So before presenting the budget, neglecting the interest of the States, you raise the prices of most articles and collect revenue in a manner most determined to a federal set up. A noted economist, Dr. Malcom Adiseshaiah says:

"The raise of administrative prices by the Centre should be completely banned. Such increases not only pre-empts the responsi-

bility of Fiscal Parliament but also deprives the States of revenue which could accrue to them if the increase is effected through excise duties."

So, I appeal to the Government to review its policy to remove the discrimination against States. The Central Government always adopts the method of taxation for increasing its revenue. But it is a unanimous view that a good Government should not indulge in this kind of revenue collection. It should open new vistas in the area of non-tax revenue in the larger interest of the nation because that will alone benefit us in the long run. But you are hell bent in increasing taxes over and again. You never try to find out better means of revenue sincerely. For example the Income-tax evaders are on the increase. Excise duty evasion is rampant. The loss revenue by such evasion is estimated at Rs. 700 crores. Excise duty amounting to Rs. 15,000 crores is awaiting judgements from various courts. Capitalists and industrialists move the courts seeking abolition or reduction of excise duty on certain items. When the orders of the courts come in their favour, they also take away the money collected by way of excise duty. In actuality this excise duty is collected from the people and in case of such abolition or reduction of duty this amount should be disbursed amongst the consumers. Since this is not practicable, the money should go to the Government to be used for the welfare of the consumers. Therefore, I urge upon the Government to plug the loopholes in the law to prevent such misuse of public money.

I want to say a few words on the attitude of the Centre towards States in the launching and execution of projects. The Centre takes on its head various projects that are exclusively under the purview of the States. The result is that the funds earmarked for certain projects are diverted to suit the interest of the ruling party at the Centre. To cite an example, in the budget of 1988-89, an astronomical sum of Rs. 5251.89 crores earmarked to be distributed to the States has been diverted and spent by the Centre in the most arbitrary manner. I charge this Government with diverting funds and resources for non-plan expenditure, depriving the States of their due share. It is again a matter of shock and surprise to look at the functioning of R.B.I. There are guidelines prescribed by R.B.I. to regulate the policies of the States regarding the loans and grants advanced to them. When the States violates these guidelines, the RBI, Planning Commission and also the Finance Ministry take serious view and deprive the States of loans and grants. But these guidelines are not followed by the Central Government. It is very strange that these norms do not apply to the Government at the Centre. It is a very dangerous phenomenon. So, I feel it is high time the R.B.I. issued guidelines to the Centre. Every year, the Ministry of Finance and the Planning Commission should report back to the Parliament the details of expenditure of every Ministry. Then alone we shall be able to see the realistic picture of our economy.

I said sometime back that the States are being neglected. I will cite only one case to substantiate my charge. Tamil Nadu has come extremely well in implementing family planning programme. Kerala and Maharashtra have also done well. But the Centre has not given any special assistance to these States.

Madam, I come from an agrarian family. I know the heart beat of farmers. We all know that the farming community comprises of 85% of the total population. But agricultural sector has been given a meagre allocation of fund in this budget. ...(*Time bell rings*)...Just two minutes.

[Shri Pashumpon Tha Kiruttinan]

The Chief Minister of Tamilnadu Dr. Kalaingnar, has given concessions to farmers to the tune of Rs. 116 crores. Short term loans and interest on mid-term and long term loans have been waived. The Governments of Andhra Pradesh and Karnataka have also done this. But the R.B.I. and NABARD oppose this kind of decisions. I fail to understand the logic behind this. If the Centre announces such decisions then the R.B.I. and NABARD have no problems, no objections. But if the States do the same thing hell breaks loose. I would have appreciated, people would have appreciated, if the Centre had come forward to advance funds to the States for these purposes. But you never did so. You announced the crop insurance scheme. That has been implemented only in few States. I ask an apposite question. What sin the other States have committed? This year you have announced subsidies on fertilizer to the agricultural sector to the extent of Rs. 5,000 crores. The subsidies are given separately to both, the industrial sector and the agricultural sector. This amount of Rs. 5000 crores is to be given as subsidy on fertilizer to the agricutural sector. But this subsidy is often misappropriated by the fertilizer industries and as a result what farmers get is only pittance or nothing at all. So the Government should see that it reaches the farmers in full. I repeat it because, usually this kind of subsidies are misdirected and misutilised by industrialists with the connivance of the concerned Government machinery.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will request the Hon. Member to complete his speech.

SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN: Just one minute more please.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is enough. Your time was only five minutes. I gave you more time because it is your maiden speech.

SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN: Yes, I am completing in a minute.

THE DEPUTY CHAIRMAN: That should not become a practice.

SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN: Therefore, the Government should see that the subsidies meant for farmers reach them in full and on time. As I conclude, I want to say a few words on Jawahar Rozgar Yojana. Because of the affliction of Hindi Jingoism you have brought in this strange name that is unintelligible to most people. I understand RLEGP, NREP, IRDP and also Jawahar. But I do not understand what is meant by Rozgar Yojana. It conveys nothing to me. Why at all this semantic play? Because you want publicity just by rechristening the existing schemes. I tell you sincerely that this scheme will create only work but not job. It will not provide employment to the unemployed as the Government claims. It will create only chaos. Since you have clubbed various schemes like NREP, RLEGP and IRDP in addition to directing Rs. 500 crores from the surcharge on income tax towards Jawahar Rozgar Yojana there is apprehension among the States in general and Tamil Nadu in particular that the above said schemes will suffer for want of adequate funds. I want the Hon'ble Minister to give an assurance that these schemes will not suffer because of the Jawahar Rozgar Yojana.

Thank you.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया : (बिहार) : उपसभापति महोदया, मैं अप्रोप्रियेशन बिल 1989 का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । हमारा मुल्क एक बड़े परिवार की तरह है । जिसमें कुछ सदस्य कमाऊ हैं और कुछ सदस्य नहीं कमाते या कम कमाते हैं । लेकिन वे भी अपना स्टेटस वैसा ही चाहते हैं जैसे उस परिवार के और लोगों का है । आज हमारे मुल्क की हालत वैसे ही है जैसे कि एक नौकरी पेशा परिवार

की होती है, जिसमें मां, बाप, बेटे, बेटियां सारे कमाते हैं । कोई कम कमाता है और कोई ज्यादा कमाता है । अगर वह कहने लगे कि मेरी तनख्वाह 2 हजार रुपये है और मैं खाने का खर्चा केवल 500 रुपये ही दूंगा और दूसरा लड़का जो मां-बाप का वफादार है और अगर वह 1000 रुपया देता है, तो जो मीट, मछली, पनीर वह खाता है, मैं भी वही खाऊंगा, ऐसा कहने लगे तो उस परिवार पर क्या गुजर सकती है? उस परिवार की बहुयें वैसी ही डिमांड करें कि मुझे वैसे ही गहने चाहिये जैसी बड़ी बहू जो कि कमाऊ है, उसके हैं । मेरा शौहर कम कमाता है इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है । मेरा घर परिवार यह है इसलिये मुझे उनको लेने का पूरा हक है । इसीलिये इस तरह के परिवार में लड़ाई खड़ी हो जाती है और वह परिवार टूटने लगता है । मां-बाप उस परिवार को जोड़ने के लिये क्या करते हैं? वे काबुलीवाले के पास जाते हैं । और घर के खर्च में जो हर महीने डेफिसेट होता है उसको मेनटेन करने के लिए काबुलीवाला से पैसा लेते हैं और अंत में एक दिन ऐसा आता है जब वह परिवार काबुलीवाला की गिरफ्त में गुलाम हो जाता है । आज हमारे मुल्क के हालात वहीं करने जा रहे हैं । कुछ राज्य सरकारें जो रीजनलिज्म की भावना उठा कर यह आवाज उठाती हैं कि हमारा इतना हिस्सा आप ले जाते हैं उस में से इतना हिस्सा हमें वापिस मिलना चाहिये नहीं तो हम चलने नहीं देंगे और हर जगह नुकताचीनी निकाल कर कहते हैं कि इतने परसेंट सरचार्ज लिया है इतने परसेंट कमाई हमारे राज्य से आपने की है वह नेशनल इनकम नहीं हो सकती है वह हमारे राज्य की इनकम है और वह हमारे पास रहनी चाहिये और उसका प्रोपर कमीशन हम को मिलना चाहिये । मैं यह पूछता हूं कि यह परिवार कैसे चलेगा, आज यह सोचने की जरूरत है। हम बड़े ध्यान से सोचें और देखें कि कम से कम हमें उस परिवार की तरह काबुलीवाला के पास नहीं जाना पड़े हमें इस मुल्क की डिमांडस को पूरा करने के लिए आ०डी०ए०, आई०एम०एफ० या वर्ल्ड बैंक के पास न जाना पड़े । हम कहीं उनकी गिरफ्त में न फंस जाए, हम कहीं फिर से इकोनोमिक गुलामी में न फंस जाएं, हमें उससे बचना है । उससे बचने के लिए हमें एकता से, निष्ठा से, भाईचारे से एक दूसरे के साथ मिल कर रहना चाहिये ।

[उपसभाध्यक्ष (श्री जनेश्वर मिश्र) पीठासीन हुए]

मैं आज आपके सामने उपस्थित होकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने खास कर जो यह नेहरू रोजगार योजना और पंचायती राज योजना लाई है मैं इसका स्वागत करते हुए यह कहना चाहता हूं कि यह एक अच्छा रास्ता अपनाया गया है । मेरे पास कई लोग आते हैं और कहते हैं कि मैं 58 साल की उम्र में रिटायर हो गया हूं फलानी जगह मैं जज था मैंने बड़े अच्छे-अच्छे केस किये हैं फलानी जगह मैं अफसर था अब रिटायर हो गया हूं इसलिये मुझे कहीं चेयरमैन सेक्रेटरी लगवा दीजिये या फिर से नौकरी लगवा दीजिये। मैं उनसे इन प्रिंसिपल यह बात कहता हूं कि आपके घर में जवान बेटा बेकार बैठा है आप उसको देखिये, आप एक और जगह को दखल करना चाहते हैं । आप उस लड़के की तरफ देखिये जो परेशान है, धक्के खा रहा है और इम्पलायमेंट एक्सचेंज के आगे लाइन लगाता है और अपने कार्ड को रिन्यू कराता रहता है लेकिन उसकी नौकरी की बारी नहीं आती है कोई इंटरव्यु लेटर नहीं आता है और आप अब भी सोच रहे हैं कि आपको रोजगार मिले । आपको बेरोजगार लोगों के बारे में सोचना है जो साढ़े चार करोड़ से अधिक लोग हमारे देश में बेरोजगार बैठे हैं उनके बारे में सोचना है जो सड़कों पर धक्के खा रहे हैं । इन बेकार लड़कों को लोग विभ्रान्त कर के गलत-गलत रास्ते पर डाल रहे हैं, कोई ड्रग स्मगलिंग में जा रहा है, कोई आतंकवाद का रास्ता अपना रहा है, कोई स्मगलर बन रहा है । इन रास्तों पर जाने से रोकने के लिए यह जो नयी योजना है कि कम से कम एक परिवार में एक व्यक्ति को हम रोजगार

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

दे सकें मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं चाहता हू कि यह जल्दी से जल्दी इम्पलीमेंट हो और यह योजना गांव में नीचे तक जल्दी से जल्दी पहुचे और उसके साथ साथ पंचायती राज के माध्यम से जो हक गांवों के लोगों को मिलना चाहिए वह तुरंत मिले और उन तक उन की वाजिब चीजें पहुंच सक और जो बिचौलिये पहले खा जाते थे उन पर रोक लगे। यह अधिकार जो राजीव गांधी देने जा रहे हैं इसका सपना वास्तव में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1976 में देखा था। तब उन्होंने 42वां संविधान संशोधन किया था और उन्होंने ख्याल रखा था कि भारत में सोशलिस्ट पेटर्न को हम अपनाएंगे। उनके दिमाग में यह बात आई थी कि हर गरीब को हर भूखे को अन्न देंगे और हर बेरोजगार को रोजगार देंगे, हर बेघर को घर देंगे और अशिक्षित को शिक्षा देंगे यह बातें उन्होंने उस वक्त सोची थी। परन्तु कुछ माहौल ऐसा था कि 1977 में जनता राज आया और अढ़ाई साल में जो नुक्सान उन्होंने हमारे सामने रखा उसको भरते हुए 1980 से 1984 आ गया हम कुछ कर न सके कुछ ऐसा कदम न उठा सके कि हम कुछ कर के दिखा सकते। 1984 में एक विदेशी चक्रांत के माध्यम से हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या हुई जिसके कारण राजीव गांधी फिर कांग्रेस पार्टी के प्रधान मंत्री हुए और पूर्ण सत्ता में आए परन्तु उस वक्त भी हालात ऐसे थे एक तरफ पंजाब जल रहा था दूसरी तरफ आसाम जल रहा था उस आग को बुझाने में काफी समय लगा इन राज्यों में डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने में काफी समय लगा और वह समय निकाल कर जब भी उनको समय मिला है उन्होंने इस मुल्क के नौजवानों के लिए इस मुल्क की जनता के लिए कुछ कर गुजरने की कोशिश की है और उन कोशिशों में यह भी एक कोशिश है नेहरू रोजगार योजना और यह भी एक कोशिश है पंचायती राज योजना। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इन कोशिशों के माध्यम से इन स्कीमों को जैसे सफल न हो सकें यह असफल हो जाएं। ये असफल हो जायें इसके लिए अभी भी कुछ चक्रांत चल रहे हैं और वे चक्रांत कहीं रीजनलिज्म के नाम से आते हैं, कहीं फंडामेंटलिज्म के नाम से आते हैं, कहीं कम्युनलिज्म के नाम से आते हैं ताकि इस मुल्क की प्रगति लोगों की आंखों तक न पहुंच सके, इस प्रगति का फल लोगों के मुहं तक न पहुंच सके, इस प्रगति का सुकून लोगों के जेहन तक न पहुंच सके। इसके पहले ही वे उसे नष्ट कर देना चाहते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं नेहरु रोजगार योजना के साथ साथ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उस तरफ कि हमारे मुल्क में करीब 417 इम्प्लायमेंट एक्सचेंज हैं और 417 इम्प्लायमेंट एक्सचेंज शहरों में हैं, जिनमें स्किलड और पढ़े लिखे लोगों के नाम दर्ज होते हैं। आज ध्यान रखने की जरूरत है कि रूरल एरियाज में जो बेकार आदमी है जो फावड़ा, खुरपी या कुदाल चलाने वाला आदमी है उसका नाम किसी इम्प्लायमेंट एक्सचेंज में लिखा नहीं होता है पर उसका नाम कहीं रजिस्टर्ड करने के लिए क्या रूरल इम्प्लायमेंट एक्सचेंज खोले गये हैं? अगर नहीं खोले गये हैं तो ये तुरंत खोलने की जरूरत है अन्यथा नेहरु रोजगार योजना जब हम लगायेंगे, जब यह गांवों में पहुंचेगी और वहां पर इम्प्लायमेंट एक्सचेंज नहीं होंगे तो हमें दुविधा में पड़ना पड़ेगा। हम सफल नहीं होंगे, हमें असफलता का चेहरा देखना पड़गा। इसलिए इसके पहले कि असफलता हमारे सामने आये हमें नेहरु रोजगार योजना में... (व्यवधान) सेपरेट रूरल इम्प्लायमेंट एक्सचेज खोलने की जरूरत है और इसके साथ साथ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जैसा कि प्रधान मंत्री महोदय ने... (व्यवधान) ये सारे बेरोजगार हो जायेंगे... (व्यवधान)... इन्हें तकलीफ हो रही है। जो नेहरू रोजगार योजना में 30 परसेंट महिलाओं के लिए भी पालन करने के लिए कहा गया है, मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से सरकार को कि कम से कम महिलाओं के लिए सेपरेट इम्पलाय-

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

मेंट एक्सचेंज भी खोले जायें जिसमें सारा रिकार्ड रह सके... (व्यवधान) और उनकी तकलीफों को जाना जा सके।

[उपसभापति महोदया पीठासीन हुईं।]

महोदया, मैं इसके साथ साथ आपको ओशन डेवलपमेंट की तरफ ले जाना चाहता हूं जहां करीब एक लाख पचास हजार स्क्वायर किलोमीटर जगह हम लोगों को एक्सक्लूसिव एक्नामिक जोन के रूप में मिलेगी लेकिन ओशन डेवलपमेंट में हमने अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जिससे हम पालीमिटेलिक नाड्यूल्स की माइनिंग का काम शुरू कर सकें। आज तक हम, लोगों से चर्चा कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, कांफ्रेंसेज कर रहे हैं... (व्यवधान) डीप सी फिशिंग, एक्वा कल्चर, एल्गी कल्चर, मेरीन कल्चर इस तरह की चीजों के लिए जो टेक्निकल मैन पावर प्लानिंग की जरूरत है उसके लिए हमारे यहां अभी सिर्फ एक ओशनोग्राफी इन्स्टीट्यूट है जो गोआ में स्थित है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके साथ साथ लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में भी इंस्टीट्यूट खोले जायें जिससे कि हम मैक्सीमम मैन पावर ट्रेन कर सकें और जिस दिन हम एक लाख पचास हजार स्क्वायर किलोमीटर में कुछ काम करने जायें तो हमें कम से कम विदेशी शक्तियों पर निर्भर न होना पड़े। हमारी स्वदेशी तकनीक हो और हम अपना काम आत्मनिर्भरता से कर सकें।

महोदया, चूंकि मैं बिहार से आता हूं तो बिहार की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बिहार के बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी भी लाइसेंसिंग के लिए पेंडिंग पड़ हुए हैं। ये क्लियर नहीं हो रहे हैं। कृपया जितने भी प्रोजेक्ट डी.जी.टी.डी. और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में हैं, तीन करोड़ से ऊपर पड़े हैं, या जितने कोटा परमिट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में पेंडिंग पड़े हैं उनको क्लियर किया जाये और साथ साथ वहां की इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए पावर जनरेशन देने की जरूरत है, सेंट्रल पावर प्रोजेक्ट्स जरूर लगाने चाहिए। महोदया, स्वर्गीय प्रधान मंत्री जी की एक कमिटमेंट थी कि बरौनी में एक पैट्रोकेमकल काम्प्लेक्स लगाया जायेगा। यह कमिटमेंट आज तक पूरी नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा कि इस पर गौर किया जाये और इसको देखा जाये। इसके पहले एक टीम भी गई थी और जमीन आदि का सारा ब्यौरा ले आई है लेकिन आज तक उस पर कोई कारगर कार्यवाही नहीं हुई है। उस पर जरा ध्यान दिया जाए। और अभी जैसा ज्ञात होता है कि तीन पेट्रो-केमिकल कम्प्लेक्स लगने वाले हैं, तो उनमें से बिहार में एक पेट्रो-केमिकल कम्प्लेक्स लगाने की मैं मांग करता हूं और वह भी बरौनी में लगे।

किसी मुल्क की गरीबी और अमीरी का तब पता लगता है कि उसके पास विदेशी मुद्रा कितनी है। हमारे मुल्क में हम एक्सपोर्ट के माध्यम से विदेशी मुद्रा कमाते हैं और आप जब भी विदेश जाएं और वहां जाकर जब हम देखते हैं कि लोग टूरिज्म के माध्यम से कितनी विदेशी मुद्रा कमाते हैं। आज हमारे मुल्क में देखने लायक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जोकि हम लोगों को दिखा नहीं सकते क्योंकि उसके लिए जो बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो होटल्ज चाहियें, या जो रास्ते चाहिए, या जो टूरिस्ट रिजार्ट्स चाहिएं, वह नहीं हैं। तो टूरिज्म को बढ़ावा देने की जरूरत है। हमारे मुल्क में चाहे कन्या कुमारी हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वह कच्छ हो या कोहिमा की सिमेट्री हो, सब कुछ देखने लायक है और इन चीजों को दिखा कर हम बहुत सारी विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं जोकि हमारे मुल्क के डिवलपमेंट में काम आ सकती है।

तो इसके लिए जो बेसिक इन्फरास्ट्रक्चर चाहिए, वह तुरंत लागू करना चाहिए और उसके लिए जितनी भी पैसे की जरूरत हो, वह जल्दी पास कहना चाहिए।

महोदया, हमारे मुल्क में बड़ी इंडस्ट्री है छोटी और लघु हैं और कुटीर उद्योग भी हैं। मैं आपका ध्यान लघु और

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

कुटीर उद्योग की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। जो लघु और कुटीर उद्योग शरणागत होते हैं बड़े-बड़े बैंक आफिशल्ज के लिए, जो बैंक आफिसल्ज टाटा को, बिरला को, गोइंका को और या फिर तोलिया को डील करते हैं, वह जब एक छोटा सा सेल्फ-इम्पलायमेंट स्कीम को लिए हुआ इंजीनियर जब उस मैनेजर के पास जाता है तो वह सही ढंग से बात नहीं करता, या उसके प्रोजेक्ट को उस तरह से डील नहीं करता।

मेरा आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को अनुरोध है कि कम से कम स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए और कुटीर उद्योग के लिए, काटेज इंडस्ट्री के लिए सेपेरेट छोटे-छोटे बैंक होने चाहिए, जिनके अफसर कम से कम डेडिकेटिड और कम से कम कमिटिड हों और वह उन लोगों की बातें सुनें, उनकी प्राबलम्स सुनें और उनको दूर करने की कोशिश करें।

इसके साथ ही साथ उनके पास कोई मार्केटिंग नेट नहीं होता, उनके पास फैक्स, टेलेक्स और टेलीफोंस उतनी जगह नहीं होते, दूर-दराज में छोटी-छोटी इंडस्ट्री लगी है। गांव में उनका मार्केटिंग सिस्टम—कुछेक मार्केटिंग नेट की जरूरत है, जो सरकार के द्वारा की जा सकती है। (समय की घंटी)

महोदया, कुछ देर पहले लोग पंचायत के बारे में बड़े फख्र से बड़ी-बड़ी बातें कह रहे थे। जो आज तक चल रहा है और जो राजीव गांधी जी लाये हैं, इसमें फर्क की बात करते हैं कि आज तक लोगों ने पंचायत में जो किया है—आज भी मैं किसी स्पैसिफिक स्टेट का नाम नहीं लेता। आज भी आप भारत के किसी भी स्टेट में चले जायें, इन्दिरा आवास योजना के नाम पर या हरिजनों की आवास योजना के नाम पर, जो भी हरिजनों के लिए बस्तियां बनाई गई हैं, वह भी उसी जमींदारी टाईम के हिसाब से शहर से बाहर या गांव से बाहर बनाई गई है। ऐसा क्यों है? यह फर्क क्यों है? हरिजनों को जब हम कहते हैं कि बीच में मिलाना है, तो उनकी बस्तियां या उनकी दुकानें शहर के बीच में बननी चाहिए, गांव के बीच में बननी चाहिए। वह बाहर क्यों हैं?

हम उन्हें मेनस्ट्रीम से क्यों बाहर रखते हैं? इन्हीं चीजों पर विचार करते हुए, राजीव गांधी जी जो नई पंचायत योजना सामने ला रहे हैं, उसका मूल कारण यह है और इसको इंप्लिमेंट करने की जरूरत है।

महोदया, जो सबसे अहम मुद्दा है, साधारण आदमी जब शाम को टी० वी० खोलता है या रेडियो खोलता है, उसे बड़ी-बड़ी बातें पता लगती हैं कि संसद में आज इतना हल्ला हुआ, इतना कुछ हुआ, वहां ऐसे-ऐसे बहस हुई। वह आम मुद्दे पर आता है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से सिर्फ एक प्रश्न करना चाहता हूं कि यह दिन प्रति दिन बाजार में जो कीमतें बढ़ रही हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए कोई कमेटी है और अगर है तो जिम्मेवार मंत्री या अफसर कौन है? कितनी मीटिंग इसकी हो चुकी है? आज की तारीख में जो बेसिक चीज है, खाने का तेल—सरसों का तेल आज 22 रुपये से लेकर 25 रुपये किलोग्राम है।

हम एक तरफ कहते हैं कि पावर्टी लाईन जो हमने ड्रा की है 6400 रुपये रूरल एरिया के लिए और 7200 रुपये अर्बन एरिया के लिए, जोकि करीब 520 रुपये रूरल के लिए आती है पर मंथ और 600 रुपये आती है अर्बन एरिया के लिए। आप सोचें कि इतने कम रुपये में एक पांच सदस्यों का परिवार कैसे घर चलायेगा जब 25 रुपये के० जी० उसे सिर्फ सरसों का तेल खरीदना पड़ता है? और तो और, परमल चावल जो पांच रुपये के० जी० है और उसके बाद सिर्फ गोल्डन सेला मिलता है जोकि 16 रुपये के० जी० है, उसके बीच में कोई चावल नहीं मिलता और जो पांच रुपये के० जी० परमल चावल है, वह आदमी के खाने लायक नहीं है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैं इतना भी कहता हूं कि यह राजीव गांधी ने नहीं कहा हुआ है कि बाजार में कीमतें बढ़ें, राजीव गांधी चाहते हैं कि ये कीमतें कम हों। पर वे

कौन जिम्मेवार लोग हैं जो कि अपनी जिम्मेवारी से दूर हटे हुए हैं और इस पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं ? मैं कहता हूं कि आज जब हम कम से कम किसान की बात करते हैं तो कहते हैं कि किसान को अपनी जीजों का मूल्य नहीं मिलता। आज की तारीख में भी एक किसान दाल जो बेचता है बिचौलिए को तो वह साढ़े चार रुपये के० जी० दाल बेचता है, पर बाजार में ग्यारह रुपये के० जी० से नीचे कोई दाल नहीं है। मसूर की दाल जो सबसे सस्ती दाल है वह 11 रुपये के० जी० है। यह ग्यारह रुपये के० जी० दाल खाकर आदमी कैसे चलेगा ? पंजाब में एक कहावत है, जो मीठ-मछला नहीं खाते हैं, उनके लिए कहते हैं, "खा दाल जेहड़ निभे नाल" कि गरीबों की हालत में भी और अमीरी की हालत में भी वही दाल तुम्हारे साथ रहेगी। किंतु यह 11 रुपये के. जी. दाल भी निभने वाली नहीं है। कितने दिन चलेगी ? मेरे कहने का मकसद यह है कि साढ़े चार रुपये से ग्यारह रुपये का जो बिचौलिए का मकसद है, जो बिचौलिए की दलाली है वह कब बंद होगी ? क्या सरकार ये दालें सीधे खरीदकर हजार में साढ़े पांच रुपये या छः रुपये के. जी. बेचेगी ? इस पर विचार करने की जरूरत है कि सस्ती जीजें हम कैसे दे सकें। महोदया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी ओर मैंने आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है और मैं चाहता हूं कि वाकई जो इंदिरा जी का सपना था कि हर भूखे को अन्न देंगी, हर बेरोजगार को रोजगार देंगी, हर अशिक्षित को शिक्षा देंगी और हर बेघर को घर देंगी, उस सपने को साकार रूप देने के लिए राजीव गांधी जी ने जो-जो कदम उठाए हैं उनका पूर्ण समर्थन करते हुए और इस एप्रोप्रिएशन बिल का समर्थन करते हुए मैं इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद।

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (Assam): Madam, Deputy Chairman, so far as this Appropriation Bill is concerned, I want to spell out my apprehensions. I feel that the current Budget and the Appropriation Bills only increase our apprehensions. In his speech, Mr. Ahluwalia mentioned the Rozgar Yojana several times—he mentioned it 25 times and I counted it—and I would like to state that my apprehension is that all these Rozgar Yojanas would create conditions for more unemployment in the country.

Madam, the honourable Minister of Finance may get applause from his partymen for presenting a populist Budget with an eye on the coming elections. The Government is only incidentally concerned about the welfare of the rural people, the rural poor, and it is showing its concern only at the fag end of the present Five Year Plan. Now, the Government has abruptly realised, in the election year, that the soul of the country really is in the villages where more than 70 per cent of the people live, out of whom about 60 per cent live in abject poverty and misery. Therefore, I cannot congratulate the Government or appreciate these moves because I think that all these colourful balloons will burst out in no time and these things will create only a ripple in the vast ocean of abject poverty in the country.

The Budget has nothing particular by way of long-term welfare measures and as such, the Budget cannot create conditions for a welfare State in the near future. As far as my State of Assam is concerned, Centre's interest is not noticeable there either in the development of the State or in the the smooth running of the State itself. Assam has been beset with a number of problems and many of them have originated because of the Central Government or have been organized by the Central Government itself. The Bodo agitation is a clear case in point. Many people, scholars with a detached judgement and objective assessment, all over the country firmly believe that the Bodo agitation in Assam is going on because of the Centre and that it

[Shrimati Bijoya Chakravarty]

is only at the instance of the Centre that it is going on.

Madam, we are passing through such a stage in our country's destiny that the Government can even sell the country's integrity for the sake of the interests of the party to get votes.

Madam, Assam is a resourceful State, but in every field of its activity the picture of its being under-developed is prominent everywhere. All the planning could not wipe out the regional imbalance in the State. The problem of regional imbalance has been in the full view of the planners ever since the beginning of Indian planning. An objective appraisal of the deficiencies in planning has not yet been made. The built-in deficiencies in the planning at strategic levels and want of synchronization of inputs are glaring. The result is huge economic loss. According to an eminent economist, the basic variable in regional planning is population. Assam is an open State having large-scale migration from the bordering States. The State is experiencing influx of population from Bangladesh and Nepal, which seriously affects her demography and also her economy. The Central Government is a silent onlooker of this problem. The silent invasion of foreign nationals creates not only a problem in Assam but since Assam is a part of India the invasion is not only on Assam but on India also.

Madam, a major portion of the per capita income of Assam flows out of the boundary of Assam. This is a sad state of affairs of my State. Like the waters of the river flowing to the sea, all the available income of Assam is extracted out of Assam and flows to other parts of the country but it cannot enrich my State. The colonial attitude of the Central Government breaks the very backbone of Assam's economy. What is worse, Madam, is that all the head offices of major commercial and industrial concerns are located outside the State. As a result... (*Time bell rings*).. I will complete within two minutes. As a result, money, services and all other facilities are enjoyed not by the people of Assam but by the people of other parts of the country. We have a cow which can give milk but the milk has not been drunk by the people of the State.

Further, flood is a major problem. The Brahmaputra is the biggest river in Asia, but the floods cannot be controlled by the meagre resources of the State. Last year Assam suffered five continuous waves of flood. Out of 18 districts 7 are completely under flood. Out of floods also the Central Government is making politics. It is a life-and-death question for the people of that part. So I feel that the Central Government should take the problem seriously and try to redress our grievances.

Madam, another point is about the Central University. It is proposed that one Central University will be set up in Assam. But with this also the Central Government is playing politics. They want to provoke one group of persons living in Assam against another so that another trouble is created there.

So far as other things are concerned, the less said the better. The railway line stops at Guwahati. It never crosses Guwahati; it stops there. Same is the case with tourism. The 'restricted area' criterion is still there. If a foreign tourist can go up to Ladakh, Madam, why can't he go to Assam? I urge on the floor of this House that this ban may be withdrawn in the case of Assam.

Madam, again in the matter of appointment of Governor, the Chief Minister is never consulted; he is simply informed.

I urge upon the Central Government on the floor of this House, Madam, to give due justice to non-Congress (I) States and not to play politics with the simple and real issues of non-Congress (I) States.

Thank you, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Minister.

SHRI B. K. GADHVI: Madam, Deputy Chairman, I am thankful to all the 15 Members who have participated in this discussion and for giving us very valuable suggestions.

Madam, when the initiator of the discussion opened up his speech, I thought that, perhaps, some new points might be emerging from his speech. But I say with a little consternation that it was a very old worn-out record being played also with a worn-out pin that for the last 40 years nothing has happened in this country. As a senior Member, if he looked back to the position of the country when we got emancipation from the shackles of the British rule, he should have realised that in the position then and now, there is a vast difference. India which had hardly any semblance of industrial development at that time and a great agrarian country but incapable of sustaining its population even in the area of food if the scarcity or the famine visited the country, is now in a position to withstand the rigours of the famine which visited this country and which was unprecedented and never experienced by the country for the last 100 years, as the records say. If this is the development on the agricultural front, then to say that the contribution of agriculture in our GDP has come down from 1951 is not a proper appreciation of the fact. Whenever you want to examine any indices about the development, both on the agricultural front as well as the industrial front then the contribution and the ratio variation between the contribution in the GDP from the various sectors are the indices to measure as to in what direction the country is going and whether development is there or not. Today, if you say, as you have said, that the agricultural contribution in our GDP in 1951 was 61 per cent and now it has come down to 24 per cent, then you should appreciate that although the production has not come down, in the other areas the contribution has gone up, mainly in the industrial areas. Industrial production has gone up, infra-structural production has gone up. And without understanding these aspects and this facet, if you go on analysing, perhaps, you may not be in a position to grapple with the situation, to grapple with the realities of the development. I would wish that the hon. Member would again give a fresh look to his thinking and his acquisition of knowledge.

Madam, as it was initiated, I would like to give some of the figures comparing 1950-51 and 1987-88. In the area of foodgrains, we had 50.8 million tonnes in 1950-51, and in 1987-88, we had 138.4 million tonnes, and we expect in 1988-89 to the tune of 170 million tonnes. You can mark the difference. In steel, in 1950-51, we were 1.04 million tonnes and today we are 10.65 million tonnes. In cement, in 1950-51, we were 2.7 million tonnes and today we are 37.3 million tonnes. In coal, we were 32.8 million tonnes at that time and today we are 190.9 million tonnes. In crude oil, we were 0.260 million tonnes and today we are 30.4 million tonnes. In power generation, we were 5.3 million kilowatts and today we are 201.9 billion kilowatts. And, therefore our GDP in 1951 was Rs. 9,177 crores, but today it is Rs. 2,93,306 crores. With these figures if you say that no development has come up in this country for the last 40 years, then perhaps, I am afraid, you have not understood the country and you have not understood the development of the country at all.

Madam, a very general criticism is levelled by almost all the Members sitting on the opposition benches about the Nehru Rozgar Yojana and they have tried to make out that it is a political gimmick, that it is an election stunt. In 1971, when Indiraji gave the Garibi Hatao programme to this country, your argument was similar. But over the years you would have found that it has now become a national programme. Now, here we are again giving another programme of Bekari Hatao under

[Shri B. K. Gadhvi]

this Yojana and that too we are amalgamating and we are making a coordinated concept of socio-economic development right from the grass-roots level of the country, i.e., from the village we are trying to harness the people right at the village level to be instrumental in developing the areas in which the poor sections of the society can have benefits and they can deliver the goods and that is why two coordinated efforts are on, one is that under this Yojana it will be amalgamated with the NREP and RLEGP, and the second one is to have a rejuvenation by putting up more tonic into the village panchayats and the panchayat structure of the country, so that we do not criticise what we are presently criticising in both the Houses, all sections, all people across the Benches, that there are leakages, that there is no proper identification of the beneficiaries, that at the other end of the tunnel light is not seen, that at the grass-roots level people are not getting the benefits, all these criticisms that we are making with a view to have a more attentive monitoring system, right up to the village level, we are again fortifying and consolidating the concept of Panchayati Raj and at the same time we are enabling panchayats with more financial powers, and we are trying to give them finances so that whatever is required to be given to the people below the poverty line, unemployed people, a new sense of enthusiasm, rejuvenation of their aspirations which is needed to alleviate the frustrations from the youth of this country, could be brought about and that is why these two concerted and coordinated efforts are on.

And that is the very reason, and that is why I say that when in 1971 Garibi Hatao programme was launched the same hue and cry was there. But later on all the Governments, including the opposition Governments in the various States had to adopt these and say that these are national programmes and give more thrust and emphasis and attention to these programmes. A day would again come when the nation would hail the Bekari Hatao programme and this rejuvenation of the Panchayati system in the country would be hailed as a hallmark and a socio-economic revolutionary step, which everybody should understand across the party line. This is the very basic feature. This is what Gandhiji said. We had many commissions on panchayats. But everybody says and it is your criticism too that planning is being done from Delhi, sitting in air-conditioned rooms and that is why they have not grappled with the reality. That is what you criticise and that is what we also feel. If the wearer of the shoe does not know where the shoe pinches, then he cannot rectify the defect. And that is why it has to be seen where the pinch is at the lowest level. And the lowest level is being given some vitality to tackle and to combat with the problems. And, therefore, to say that this yojana would not work properly or that this Yojana has got another motive, would not be the right thing to do. Personally, I would say that we all are political parties. What is the fundamental duty of a political party? The fundamental duty of a political party in our democracy is that it should deliver the goods to the liking of the people. If the people like a particular

6.00 P.M. programme, then it is no use saying that it is political gimmicks or election motivated programme of this programme or that programme. That is why I say that when we speak about the realities, when we speak of the programmes, we have to speak also in the context that we are running a political system in the country, a democratically elected Government, and a political system which sustains democracy, which strengthens democracy, and we are running that system. That system could best be run when the political aspirations of the people are fulfilled, when the people's desires are met

with and when programmes, particularly for economic emancipation of the people, to ameliorate the conditions of the down-trodden are taken up. If we are able to bring about those conditions, then only we can have justification in saying that we are a political party, and that is what we are doing. That is the reason why despite your hue and cry, people of this country have got faith in this party for the last 40 years, since independence, and even before independence they had faith in our party. We do not grow like mushroom. We have got a sustained policy and programme. Not only after independence, even prior to independence there was a planning committee in the Congress party itself, and we gave planning to this country, from which infrastructure has come up today.

We are criticising pubic sector under takings. When their conception was made in the past, profit was not the only motive. The motive was to create an infrastructure so that country can take a leap forward, and that is why we said that public sector undertakings must have a commanding height in our economy. Today also that concept is constant; but we certainly wish that wherever there are deficiencies, if the public sector undertakings are not coming up to expectations of the people, if their contribution to the national exchequer is wanting or falling short, then certainly there should be something to be done and I would inform the House that for a constant review and monitoring of the functioning of the public sector undertakings, a committee is there headed by the Cabinet Secretary, to look into all these aspects. Some of the public sector undertakings have not even no profit motive, but they were not established, for profit. Take for example textiles. Why did we nationalise it? It was not because they were sick units which could not give us profits but we had to take care of the labourers also Similar is the case with other industries where we give them financial assistance and we restructure their financial conditions. It is not merely for the purpose of making profits. It is also for the purpose of helping labourers who would otherwise be rendered unemployed and be put to great distress and difficulty. So, you kindly view the elephant as it is being viewed by the man who has got eyes to see, and not like a blind man who feels one side of it and says it is a pillar, and the other blind man says it is like a wall and the third man says something else. A totally comprehensive picture has to be taken of it and unles we do it, we cannot have a fair idea about it.

I know it is your duty to criticise the economy. If we go wrong, it is your duty to point out and be a watchdog and tell the Government where it is failing. That is your duty. But at the same time, to cast away totally all sense of appreciation and go on hurling criticism for everything will not be fair... (*Interruptions*)

श्री राम अवधेश सिंह : आप जो कह रहे हैं...

SHRI B. K. GADHVI: You cannot understand it. Kindly keep shut.

श्री राम अवधेश सिंह : आपकी समझ में नहीं आता है... (**व्यवधान**)

उपसभापति : आप उनको डिस्टर्ब मत किजिए बोलने दीजिए...

SHRI B. K. GADHVI: It is not within your competence to understand economics.

Therefore, what I want to submit is, when we view economy in its totality, only then we can get a true picture. Today, what is our stance? People talk about debts and other things; external debts and internal debts. Do we not appreciate resilience of our own economy which had withstood the pressures from many factors, external and internal both? Even then India was in a position to say to the IMF that we do not want any special assistance. India can do away with it. Is there any other developing country in the world to do so? They would kneel down and buckle down before

[Shri B. K. Gadhvi]

pressures, economic pressures and levers, and that is why you see what is the Indian position as compared to other countries position, because economy also has a bearing on the trend of prices. You talk about external debt, internal debt, debt trap and other things. I would like to give a comparison here. If you take the four years' average, 1985 to 1988, in the Latin American countries, the price rise is 136.83 per cent but in India it is 8.15 per cent. And you say that we are in a debt tarp, that there is inflation, etc. You say that we should contain inflation. But I would like to point out that inflation is under control. Prices are also under control. Not only that. We have our prestige. Everybody knows our capacity to withstand and to abide by our commitments; it may be foreign debt or it may be internal debt. People have the confidence in us that we can repay whatever we borrow. This confidence is of great value. This confidence comes not only from the other things but it also comes from the management of the economy. India has never defaulted. India is capable.

Of course, it is true that there is adverse balance of trade. Our imports outpace the exports. But we are augmenting our exports. (*Interruptions*) You cannot understand.

श्री राम अवधेश सिंह : लेटिन अमेरिका का आपने बताया कम्पेयर कर दिया तो दूसरे देशों का भी बतायें।

श्री बी० के० गढ़वी : आप लाइब्रेरी में पढ़ लीजिए । (व्यवधान)

श्री राम अवधेश सिंह : आप ज्यादा समझता हूं । (व्यवधान)

उपसभापति : राम अवधेश जी आप बैठ जाइये । मंत्री जी बोल रहे हैं डिस्टर्ब मत कीजिए ।

SHRI B. K. GADHVI: It is true that so far as the balance of payments position is concerned, we have to be cautious. We cannot afford to be spendthrift. We cannot afford to be prodigal. At the same time, we are making a dent in the international market today, not only in the conventional markets and in relation to conventional commodities but also in non-conventional markets and in relation to non-conventional commodities. But for upgrading the technology, for improving the expertise, if we have to import, we have to import for the larger purposes in future. After all, we have to lay the foundation, the base. On that solid base, India can leap forward, At the same time, I would like to assure the House that Government is alive to the fact. Therefore, we are again recasting the whole thing. In regard to unessential items on the OGL, there is a scrutiny on by a committee. They will try to scrutinise the areas where we can curb the imports. But if there is an export-oriented concept in any of the imports or it is an essential item for upgrading the technology or it may be project imports or it may be engineering goods import or imports of other types of technology or expertise or collaboration etc., certainly we have to import. We have to upgrade the technology. We cannot shut our windows. We cannot afford to prevent fresh winds coming from outside. I would again say that we are aware of it. I hope our exports which are now picking up would be in a more favourable position next year.

Madam, as I said, not many points have been made by hon. Members who spoke on this Bill. But one Member, Mr. Raoof Valiullah, said that the pattern that we are changing has created some problem for the States. He said that the devolution of funds meant for the States has come down. in regard to small savings and other things. I believe, his apprehension is misconceived. After all, we have introduced many other things like the Indira Vikas Patra, the Kisan Vikas Patra, the Monthly Income Scheme, the National Saving Scheme, etc. In 1988-89, small savings have substantially exceeded even the revised estimate of Rs. 4,600 crores. The original estimate was only Rs. 3,700 crores. Therefore, in regard to the share of

the States in small savings or in relation to schemes like the Indira Vikas Patra etc., the States have not suffered at all. That was one view at that time. But later on, we rectified it. Therefore, there should not be any difficulty for the States to manage their economy. But I would like to submit one thing that we have got the federal structure and hence all our States are as important limbs of the body as the Central Government is. Therefore, the rising tendency in the States not to mop up or create their own resources and always to depend upon or to ask the Centre to come to their help, even for the affairs which they are supposed to manage, is not a healthy trend from the point of view of a strong economic nation.

SHRI RAOOF VALIULLAH: I did not say that. I said give us the royalty that is due to us.

SHRI B. K. GADHVI: I do not say that you have said this. This is our general observation that all the States are supposed to manage their economy well and even for the funds which go to them from the Centre either through Centrally sponsored schemes or other schemes they are the implementing agencies. We have got our own limitations and constraints. We cannot go to the grass-root level and implement particular schemes. Therefore, States have to be more vigilant, districts have to be more vigilant. Members belonging to all political parties have to be more vigilant so that there are no leakages, so that the corrupt people and the black sheep are eliminated from the field. That has to be the concerted effort. It is no use just to go on sermonising or advising and telling that this or that should or should not be done. If wishes were horses then the beggars would ride. So, I wish to say that States have also to manage. As the Madam from Assam has said, if they do not create, if they feel shy of augmenting their resources, if they take a populist stance, perhaps politically it will be in our favour but economically it cannot give us a sound base.

श्री राम अवधेश सिंह : फेट यूटिलाइजेशन के बारे में साफ करिये ।

श्री बी० के० गढ़वी : आपको जवाब मैं नहीं दे सकता हूं । आप तो बड़े माहिर हैं, होशियार आदमी हैं ।

श्री राम अवधेश सिंह : फेट यूटिलाइजेशन के चलते पूर्वी भारत का पूरा शोषण हो गया है । बिहार, उड़ीसा का शोषण हो गया है ।

श्री बी० के० गढ़वी : संस्कृत में एक कहावत है, सुनोगे ।

लभते सिकता सुतेलम् वित्,
मूर्खस्य चित्तम् नालाखेत ।

अर्थात् बालू से तेल निकल सकता है, लेकिन आप जैसे आदमी को समझाया नहीं जा सकता है ।

श्री राम अवधेश सिंह : मूर्ख को मूर्ख ज्यादा दिखाई पड़ते हैं । जो मूर्ख खुद होता है वह दूसरों को भी मूर्ख समझता है ।

SHRI B. K. GADHVI: I do not know on what premise the Members were attacking that the Budget was prepared by the bureaucrats. Of course, bureaucracy is a part of our system. We cannot do away with them. They furnish us the data. They give us suggestions and ideas, but ultimately it is the policy decision which is to be taken by the elected Government. All the concepts about programmes and other things, if they belong to bureaucrats, why do you accuse us of not doing or implementing these things? When we go in the field for elections, you will not say that the bureaucracy has done this, you will say that this Government, Mr. Rajiv's Government has committed this error and that error and we will have to reply also. We would not say that it was done by bureaucrats. So, all the policies, programmes directions and

[SHRI B. K. GADHVI]

everything, they belong to the political executives of the country, and the political executives, in fact, are the Prime Minister, the Cabinet, the Council of Ministers, etc. Therefore, it does not behove senior Members like Mr. Yadav and Mr. Sinha to say all these things. I can understand about other Yadav saying anything which hardly has any sense, but for them to say like this is not proper.

श्री राम अवधेश सिंह : फ्रेट यूटिलाइजेशन के बारे में आप जवाब नहीं दे सकते हैं । आपमें हिम्मत है तो बोलिये ।

SHRI B. K. GADHVI: Now Mr. Sinha has made two points which I think I must dwell upon. Firstly, he says that we have given instructions to make a 5 per cent cut and in that case we should have asked for 5 per cent out in the Appropriation Bill also. It is a technical subject that Mr. Sinha has raised. I would say that we have not given instructions that there should be a five per cent cut in the amounts allocated to the various Ministeries. What we have said is that they should keep five per cent as reserve, without spending, and that we would be monitoring their expenditure month by month and we have set up a Committee for that. The constant criticism has been that in the last lap of the year, in the last month, there is a lot of rush of expenditure. With a view to preventing it and seeing that every amount is utilized for the purpose proper for which it is meant, we have said that they will have to keep five per cent as reserve, but not as a cut (*Interruptions*). Therefore, to say that a five per cent cut should be there in the Appropriation Bill also, is not a proper approach.

Another point he made was that we have swerved from our industrial policy and we have given certain projects on a turnkey basis. That is not swerving. Some of the projects are such that we have to go in for global tendering and, in a competitive market, if a man from another country gives his tender and if it is justified we may give it to him; there is nothing wrong about it. It will be appreciated that our Indian Railways and others are doing some jobs in other countries on a turnkey basis. It does not mean that we have deviated or swerved from our industrial policy or that we have given the go-by to it. Mr. Sinha has gone out. Perhaps he should have understood this matter.

Now, another matter which has been made was about gas. Mr. Raoof Valoullah raised... (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please don't disturb when the Minister is replying.

श्री राम अवधेश सिंह : यह हमारे लिये जीवन मरण का सवाल है आपको क्या मालूम है ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please, everybody should keep quiet.

श्री राम अवधेश सिंह : फ्रेट एक्विलाइजेशन के चलते बिहार का इतना शोषण हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता है । हजारों करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है । इस फ्रेट एक्विलाइजेशन के ऊपर आप ... (व्यवधान)... मैं तो मंत्री महोदय से पूछ रहा हूं । ये लोग नाहक बोल रहे हैं । फ्रेट एक्विलाइजेशन के चलते बिहार का हजारों करोड़ रुपये से प्रति साल शोषण हो रहा है... (व्यवधान)... मैं चाहता हूं कि आप इसको स्पष्ट कर दें ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, you don't reply to him.

SHRI B. K. GADHVI: So far as the question of royalty is concerned, the States of Assam and Gujarat have asked for ad hoc money also but we have not acceded to that. The matter is under consideration of the Committee and I am hopeful....

(*Interruptions*) ,

श्री राम अवधेश सिंह : फर्स्ट यूटिलाइजेशन को पहले बात बतायें।

उपसभापति : राम अवधेश सिंह जी, आप बैठ जाइये।

श्री राम अवधेश सिंह : जवाब दिलवाइये।

उपसभापति : वे क्या कर रहे हैं ? जवाब नहीं दे रहे हैं क्या ? आप कान में लगाकर सुनिये।

SHRI B. K. GADHVI: Now, another point, Madam. Mr. Sinha drew attention to a press report and said that more projects would not be cleared because of constraint of foreign exchange. But I would like to clarify that there is no truth in the report that Government has decided on suspending of projects because of constraint of foreign exchange. No such orders have been issued by the Government. So, whatever the press reports are, they are not based on facts.

The honourable DMK Member who made his maiden speech spoke about the oil pool surplus. There is nothing wrong about it. The year before also it was done. He said that the balance should be distributed among the States. In that case, I would say we are giving subsidies on food, fertilizers, exports and other things.. We never asked them to bear a share of it. Likewise in this matter also we cannot give a share. That money was lying idle and we have spent it.

Lastly one basic feature I would cover and then close, and that is about the deficit to which Mr. Yadav, while initiating the discussion, referred. Let me tell him how much fruitful our exercise has been. In 1986-87, our estimated budget deficit was Rs. 3,703 crores, the revised estimate was Rs. 3,703 crores and actuals came down to Rs. 3,261 crores. It came down from the revised estimate. For 19877-88 it was Rs. 5,688 crores. The revised estimate was Rs. 6,080 crores. The actual came down to Rs. 5,816 crores. For this year, that means last year, 1988-89, I am happy to inform the House that the Budget estimate of the deficit was Rs. 7,484 crores, the revised estimate was Rs. 7,940 crores, and the actual deficit has come to Rs. 5.810 crores. That means Rs. 2,000 crores less than the revised estimate. This is the actual I am giving because the figures recently we got. This would indicate that we are all alive to see that the deficit is brought down. We are also alive to the fact that the non-Plan expenditure should not exceed the revenue receipts. But at the same time, we also have to appreciate that so far as the non-Plan expenditure is concerned, the moment you create an asset on the Plan and transfer it to the non-Plan side, then, on maintaining and running that asset you have to spend, and if you do not spend, then, perhaps, you cannot have the utility of that at all.

Mr. Jaswant Singh spoke about defence. It has already been made clear that although the defence budget has been frozen to Rs. 13,000 crores, if need arises, then, defence would never feel the want of money. But in certain areas without compromising with the defence preparedness, we have been able to achieve more economy. That everybody had demanded. It is not that we have compromised anywhere on the defence preparedness or on the defence projects. But it is a very huge organisation from which you can scan out something and have a little more savings. That exercise has been done, and it is because of that that we have been in a position to continue the defence budget. But I reitrate that if the country needs more allocation for the defence services, if the need arises, then . funds would not be wanting, there would not be any constraint of funds.

Madam, with these words, I commend the Bill. Perhaps, I have met all the points. I thank again all the Members.

श्री मोहम्मद अमीन : इंडो इविवलाइजेशन के बारे में तो कहिये (व्यवधान)

उपसभापति : अब जवाब हो गया है। (व्यवधान)

Mr. Amin, there is a procedure. Perhaps you are a new Member. You should have read the rules. There is a procedure in the House. When a Minister is speaking, you are not to disturb. Also, you cannot ask questions directly. If you want, you request the Chair. I will not allow this unruly business in the House, that while the Minister is on his legs, everybody is having a dialogue. This cannot be allowed in the House.

श्री राम अवधेश सिंह : ऐसा बराबर होता रहा है।

उपसभापति : गलत हो रहा है। आपके रहते होता है और कोई नहीं करता।

Only you do it. If you want, you please ask that you have a point which has not been answered.

The Minister will answer it if he feels like doing so. You just cannot get up and create an unruly scene in the House. I would not allow this.

The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1989-90, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration.

Clauses 2 to 4 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Valiullah, I had warned everybody that while the Bill is being passed, nobody should disturb the House.

SHRI B. K. GADHVI: I beg to move:

"That the Bill be returned."

The question was put, and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House adjourns till 11-00 o' clock tomorrow.

The House then adjourned at twenty-five minutes past six of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 4th May, 1989.

MGIPMRND—309 RS—RS-I—14-12-89